epaper.dehatsandesh.com

3 जम्मू-कश्मीर में सेना चरण और अग्रिम क्षेत्र भ्रमण का शुभारंभ

5 क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने सऊदी टूरिज्म कैंपेन का चेहरा

8 यू.ए.ई. में भारत के राजदूत होंगे दीपक मित्तल

मौसम जम्मू — न्यूनतम 16 — अधिकतम 25

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष 22, जमू तवी, अंक 217 | जमू तवी, बुधवार 03 सितबर 2025 | मूल्य- 3 रूपये (लेह) 4 रूपये पृष्ठ -8

किसानों, गामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दें बैंकः मुर्मु

चेन्नई 02 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कि समय पर और किफायती ऋण प्रदान करके, वित्तीय साक्षरता प्रदान करके और कृषि-तकनीक पहलों को समर्थन देकर, बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं।

श्रीमती मुर्मु यहां सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। 'स्वदेशी बैंकिंग की विरासत 120 वर्षों का उत्सव' शीर्षक के इस समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल एन आर रवि , केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमिलनाडु सरकार की समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री पी गीता जीवन उपस्थित थीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में

बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट सिटी तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई क्षेत्र) को विकास के इंजन में बदलने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे बैंकों को वंचित और हाशिये पर पड़े वर्गों की मदद के लिए भी कदम उठाने चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को बैंकिंग सेवाओं से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बैंकिंग उद्योग इसकी विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य में, लोगों की आकांक्षायें काफ़ी बढ़ी हैं। बैंकों की भूमिका वित्तीय लेन-देन से कहीं आगे बढ़ गयी है। बैंक केवल धन के संरक्षक नहीं हैं। आज वे विविध वित्तीय सेवायें प्रदान करते हैं। वे समावेशी और सतत विकास में भी सहायक हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक स्तम्भ 'वित्तीय समावेशन' का है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को किफायती वित्तीय सेवायें सुलभ एवं सुनिश्चित हों। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंक बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में, एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहां औपचारिक बैंकिंग तक सीमित पहुंच है। उन्हें कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सिटी यूनियन बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

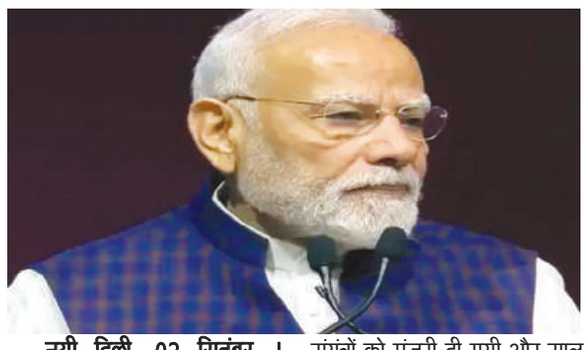

सेमीकंडक्टर की हमारी यात्रा देरी से शुरु हुयी, लेकिन अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती : मोदी

- प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया
- भारत की सबसे छोटी चिप बहुत जल्द दुनिया को सबसे बड़े बदलाव की ओर ले जाएगी

नयी दिल्ली, 02 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भले ही सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत की यात्रा देरी से शुरू हुई है, लेकिन अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। श्री मोदी ने यहां द्वारका स्थित यशोभूमि में तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। साल 2021 में सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत हुई थी और साल 2023 में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए मंजूरी प्रदान की गयी। साल 2024 में और संयंत्रों को मंजूरी दी गयी और साल 2025 में पांच और परियोजनाएं मंजूर की गयीं। कुल 10 परियोजनाओं में 18 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत बैकएंड से निकलकर पूर्ण शक्तिशाली सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर बढ़ रहा है। भले हमारी यात्रा देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि टाटा और माइक्रोन ने टेस्ट चिप बनाने शुरू कर दिये हैं और पहला वाणिज्यिक चिप भी इसी साल बाजार में आ जायेगा। प्रधानमंत्री ने घरेलू और विदेशी कंपनियों से इस क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार की नीति अल्पकालिक संकेत नहीं, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, आपकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया।

उन्होंने कहा कि दुनिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाली प्रतिभाओं में 20 प्रतिशत भारतीय है। देश के नवाचारों और स्टार्टअप कंपनियों से उन्होंने अपील की कि वे आगे आएं, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, श्री जितिन प्रसाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सेमीकॉन इंडिया- 2025, 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला तीन दिवसीय सम्मेलन है। यह भारत में एक मज़बूत, उदार और दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

इसमें सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फ़ैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के अंतर्गत पहलों, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के प्रारूप का भी उल्लेख किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने जम्मू में बाढ़ के बाद पुनर्स्थापना उपायों की समीक्षा की

गृह मंत्री के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई पर दिया ज़ोर

म्मू 02 सितंबर। हाल ही में आई बाढ़ से हुई क्षति का जायज़ा लेने के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के बाद, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रशासनिक सचिवों और संभागीय प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दौरे पर आए मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के त्वरित और समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुँचाने और आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली आपूर्ति व पेयजल की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच समन्वय की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने सड़क संपर्क पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों को युद्धस्तर पर शीघ्र बहाल किया जाए, क्योंकि सड़कें अन्य सभी राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों की रीढ़ हैं।

मुख्य सचिव ने संबंधित संभागीय और ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त ढाँचे की बहाली के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार की जाए और निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।

जनस्वास्थ्य पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जल आपूर्ति से पहले सभी जलस्रोतों की जाँच की जाए, ताकि जलजनित रोगों के प्रकोप को रोका जा सके।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रभावित गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी निर्देश दिए, जिनमें चिकित्सक दल आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण करें और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक ढाँचों.विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, पुलों और सरकारी कार्यालयों.का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए, ताकि इनकी संरचनात्मक स्थिरता और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि ये सभी निर्देश सीधे केंद्रीय गृह मंत्री से प्राप्त हुए हैं और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता व गंभीरता के साथ लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने आगे यह भी दोहराया कि सरकार प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के साथ-साथ दीर्घकालिक मजबूती और सुरक्षा की दिशा में भी कार्य कर रही है। इसके लिए बेहतर अवसंरचना योजना, आपदा प्रबंधन और रोकथाम उपायों के माध्यम से भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक स्थित ड्रोन गिराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश

4 गिरफ्तार -बीते दो महीने में करीब 30 किलोग्राम हेरोइन ड्रोन से भेजी गई

कठुआ, 02 सितंबर । सीमा पार ड्रोन गिराने की गतिविधि को एक बड़ा झटका देते हुए एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना के मार्गदर्शन में कठुआ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस गिरोह को चला रहे थे।

जानकारी के अनुसार बीते 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर के छन्न टांडा गाँव में ड्रोन द्वारा एक मादक पदार्थ का पैकेट गिराए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस और बीएसएफ द्वारा त्वरित कार्रवाई करने पर लगभग 447 ग्राम अफीम बरामद की गई। इस पर थाना हीरानगर में एनडीपीएस अधिनियम 18/08/19 और यूएपीए की धारा 13 के तहत प्राथमिकी 107/25 दर्ज की गई और जाँच शुरू की गई। जाँच के दौरान स्थानीय गवाहों की मदद से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से भेजी गई खेप को उठाना और नशा तस्करों तक पहुँचाना था। इन व्यक्तियों की पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी अमृतसर और अर्शदीप सिंह उर्फ राजा पुत्र परमजीत सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब के रूप में हुई है। दोनों जिला सांबा के घगवाल में एनएचएआई परियोजना में कार्यरत थे। इससे 411 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई, जिसे इन कूरियरों ने यह कहकर अपने पास रखा था कि अगली बार तस्करों को इसकी आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा कूरियर द्वारा बताए गए पहचानकर्ताओं की मदद से और सांबा व कठुआ क्षेत्र के सभी नशा तस्करों के डेटाबेस को स्कैन करके, हेरोइन प्राप्त करने वाले की भी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्कर की पहचान फिरोज दीन उर्फ अल्लू पुत्र सह्या निवासी राजबाग कठुआ के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के संपर्क में था। आगे के खुलासे से पंजाब के तरनतारन से ड्रग किंगपिन/फाइनेंसर की गिरफ्तारी हुई। वह उसी पाक स्थित तस्कर के संपर्क में भी था और हवाला के जरिए नशीले पदार्थों की आय को पाकिस्तान भेजने के लिए जिम्मेदार था। नशा तस्कर और नशा किंगपिन दोनों से हेरोइन और नकदी बरामद की गई। जांच में पता चला है कि ये आरोपी कट्टर अपराधी हैं और पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ड्रोन के जरिए गिराई गई 30 किलोग्राम से अधिक हेरोइन आसपास के जिलों के नशा तस्करों को पहले ही सप्लाई कर चुके हैं।

जमू पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, बढ़ रहा नदियों का जलस्तर

जम्मू, 2 सितंबर । जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार दोपहर प्रशासन ने ताज़ा बाढ़ चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार उधमपुर में तवी नदी का जलस्तर मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 18.31 फीट तक पहुंच गया, जबकि अलर्ट स्तर 15 फीट है। खतरे का स्तर 20 फीट तय किया गया है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो निचले इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं सांबा ज़िले में बसंतर नदी का जलस्तर भी मंगलवार दोपहर 2-27 बजे तक 4 फीट के अलर्ट स्तर पर पहुंच गया।

अगले 60 घंटों में जम्मू-कश्मीर में व्यापक बारिश की उम्मीद : मौसम वैज्ञानिक

श्रीनगर, 2 सितंबर । मौसम विज्ञानी ने मंगलवार को अगले 60 घंटों में पूरे जम्मू-कश्मीर में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की। स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैज़ान आरिफ ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है हालांकि कभी-कभार रुकावटें आ सकती हैं। फैज़ान ने कहा कि नदियों और नालों में जल स्तर काफी बढ़ने की उम्मीद है। कुछ क्षेत्र संभावित रूप से बाढ़ के खतरे के स्तर को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर क्षेत्र में भी बारिश की उम्मीद है लेकिन जम्मू की तुलना में कम तीव्रता के साथ। हालांकि कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से पीर पंजाल पहाड़ों और कुलगाम शोपियां और अनंतनाग के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फैज़ान ने कहा की इस अवधि के दौरान झेलम नदी का जल स्तर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है। पूर्वानुमानकर्ता ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर कभी-कभी तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आकस्मिक बाढ़ और बादल फटने से इंकार नहीं किया जा सकता है जबकि दोनों क्षेत्रों में नदियाँ और नदियाँ उफान पर हो सकती हैं। पर्वतीय दर्रे भूस्खलन और पत्थर गिरने के प्रति संवेदनशील बने रहने की संभावना है। निवासियों और यात्रियों को तीव्र वर्षा की इस अवधि के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

राजोरी में भारी बारिश से मकान गिरने से एक व्यक्ति घायल

जम्मू,, 2 सितंबर । राजोरी जिले के पोट चौधरी नार में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक आवासीय मकान गिर गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना सुबह के समय हुई और लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में खतरे की स्थिति को उजागर करती है।

घटना की सूचना मिलते ही राजोरी के विधायक इफ्तिखार अहमद तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज राजोरी पहुंचे जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा था।

विधायक ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया कि घायल को हर संभव बेहतर इलाज मिल रहा है।

विधायक इफ्तिखार अहमद ने पीड़ित परिवारों से भी बात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर घायल व्यक्ति और उनके परिवार को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

बनी बसोहली और बिलावर में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर

कठुआ बसोहली बनी मार्ग वाया लखनपुर एक महीने से बंद

कठुआ, 02 सितंबर। कठुआ जिले की पहाड़ी तहसील बनी बसोहली और बिलावर में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। नदियों नालों के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

कठुआ में मंगलवार को दिनभर हुई बारिश से जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर भरी नुकसान, रास्ते बंद आदि की खबरे आई हैं। भारी बारिश से बनी-बसोहली मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण बनी बसोहली सड़क संपर्क टूट चुका है। वहीं पिछले एक महीने से कठुआ बसोहली वाया लखनपुर सड़क पूरी तरी से बंद है। बसंतपुर के समीप हाल ही में बने नए पुल के पास सड़क टूट चुकी है जिससे लखनपुर के रास्ते बनी-बसोहली और बिलावर जाने वाली सड़क बंद पड़ी है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।.

जावेद राणा द्वारा पुंछ में पुनर्स्थापना प्रयासों की समीक्षा

जम्मू 02 सितंबर। हाल ही में आई बाढ़ों के कारण पुंछ ज़िले में हुई व्यापक तबाही के बाद, जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय कार्य मंत्री, जावेद अहमद राणा ने एक विस्तृत वर्चुअल बैठक के माध्यम से राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मंत्री ने पुनर्स्थापना उपायों की प्रभावी योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया कि बहाली कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और विभागाध्यक्ष स्वयं ज़मीनी स्तर पर निगरानी करें ताकि कार्यों की गति तेज़ हो सके।

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि विशेषकर दूर-दराज़ और संवेदनशील क्षेत्रों में प्राथमिक ध्यान पेयजल, बिजली, सड़क संपर्क, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने पर होना चाहिए। मंत्री ने प्रभावित परिवारों के लिए एक समग्र और समावेशी पुनर्वास रणनीति बनाने तथा भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक रोकथाम उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुआवज़ा और राहत सहायता शीघ्र और न्यायसंगत ढंग से दी जाए, खासतौर से उन परिवारों को जो सबसे अधिक प्रभावित और जोखिमग्रस्त हैं।

शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को रेखांकित करते हुए, राणा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों का विस्तृत संरचनात्मक ऑडिट कराने पर बल दिया। उन्होंने विभागों को कमजोर स्कूल भवनों की पहचान करने, त्वरित मरम्मत करने और संस्थानों को छात्रों व स्टाफ की सुरक्षा हेतु दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

क्षति आकलन के तहत, उपायुक्त पुंछ, अशोक कुमार शर्मा ने मंत्री को जानकारी दी कि ज़िले में 18 विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीमा-दीवारों को नुक़सान पहुँचा है, जबकि 4 विद्यालयों की तत्काल मरम्मत आवश्यक है ताकि पढ़ाई सुरक्षित ढंग से जारी रह सके। इन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है।

सड़क अवसंरचना पर जानकारी देते हुए बताया गया कि मेंढर उपमंडल की 71 सड़कों में से 65 को वाहन योग्य बना दिया गया है, जबकि शेष पर कार्य जारी है। सुरनकोट उपमंडल में 10 सड़कों को नुक़सान पहुँचा है, जहाँ बहाली कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। अधिकांश पीएमजीएसवाई योजनांतर्गत सड़कें भी बहाल कर दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और सुरक्षा कार्यों की क्षति को देखते हुए मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को विशेष मामले के रूप में मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य सौंपने के निर्देश दिए, ताकि सबसे प्रभावित गाँवों में राहत व पुनर्वास तेज़ी से हो सके।

स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उपायुक्त ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

अर्थराइटिस

निराशा को बदलें आशा में

जोड़ों में सूजन और दर्द से संबंधित अर्थराइटिस नामक रोग के अनेक प्रकार हैं। इस मर्ज के कारण पीड़ित व्यक्ति का चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। दुनियाभर में खासकर भारत में अर्थराइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी के बढ़ने पर चिंता जतायी है।

ऑस्टियो अर्थराइटिस को दें आघात

आम तौर पर जिंदगी के उत्तरार्द्ध (50 साल की उम्र के बाद) में जोड़ों (ज्वाइंट्स) की कार्टिलेज के घिसने या उनमें टूट-फूट होने के कारण ऑस्टियो-अर्थराइटिस की समस्या पैदा होती है। यह साइनोवियल ज्वाइंट्स से संबंधित बीमारी है, जो धीरे-धीरे शरीर पर अपना दुष्प्रभाव दिखाती है। इस रोग के बढ़ने पर सबकॉन्ड्रल नामक हड्डी मोटी हो जाती है, जिस कारण ऑस्टियोफाइट (हड्डी का एक अंश) का निर्माण होने

लगता है और अंततज्जोड़ टेढ़े-मेढ़े या तिरछे हो जाते हैं।

नई रिसर्च के नतीजे

- कुछ खास जेनेटिक कारण भी ऑस्टियो-अर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार हैं।
- मैनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनों के स्तर में बदलाव से महिलाओं में ऑस्टियो- अर्थराइटिस के होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- मोटापे के कारण जोड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण इन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोटापे से ग्रस्त रहने की संभावना ज्यादा रहती है।

लक्षण

- देश की महिलाओं में ऑस्टियो-अर्थराइटिस का असर उनके हाथों और घुटनों पर कहीं ज्यादा पड़ता है।
- जोड़ों में दर्द और सूजन होना।
- जोड़ों में जकड़न होना या फिर इनका जाम होना।
- चलने-फिरने और दैनिक कार्य्यो को करने में दिक्कत महसूस होना।
- फर्श पर बैठने-उठने और पाल्थी मारकर बैठने में परेशानी महसूस करना।

जांचें- विशेषज्ञ डॉक्टर जोड़ों की स्थिति का क्लीनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि जोड़ किस हद तक विकारग्रस्त हो चुके हैं और पीड़ित व्यक्ति की दिनचर्या पर कितना प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा प्रमुख जांच एक्सरे है। रक्त परीक्षण भी कराए जाते हैं। रक्त परीक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि किसी अन्य कारण से मरीज को अर्थराइटिस तो नहीं है।

शुरुआती इलाज - रोग की शुरुआती अवस्था में पेनकिलर्स का इस्तेमाल, मरहम या जेल, गर्म पानी से सिकाई या मालिश करना, सर्पोर्ट्टिग उपकरण और व्यायाम कराए जाते हैं। इसके अलावा रोगी को कुछ विशिष्ट कॉन्डोजेनिक मेडिसिन्स (कार्टिलेज का पुनर्निर्माण करने वाली दवाएं) दी जाती हैं।

सर्जिकल इलाज- रोग की शुरुआती अवस्था में आर्थोस्कोपिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वाइंट डिब्राइडमेंट (जोड़ के अंदर पालिश करना)आदि से कुछ हद तक राहत मिलती है।

हाई टिबियल ऑस्टियोटॅमी - अगर रोग का प्रकोप गंभीर अवस्था में नहीं हैं, तो और मरीज की उम्र लगभग 50 या 55 से कम है, तो इस स्थिति में हाई टिबियल ऑस्टियोटॅमी से राहत मिल जाती है और इस प्रकार जोड़ प्रत्यारोपण की संभावना स्थगित हो जाती है।

अंतिम कारगर इलाज - जब इलाज के उपर्युक्त विकल्पों से ऑस्टियो-अर्थराइटिस से ग्रस्त व्यक्तियों को राहत नहीं मिलती, तो इस स्थिति में पूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण (टोटल ज्वाइंट्स रिप्लेसमेंट) किया जाता है। ऐसे प्रत्यारोपण में प्रमुख रूप से घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण को शामिल किया जाता है। घुटना (नी)और कूल्हा (हिप) प्रत्यारोपण के क्षेत्र में नवीनतन तकनीकों से युक्त ऐसे कृत्रिम घुटने व कृत्रिम कूल्हे आ चुके हैं, जो कुदरती स्वस्थ घुटने व कूल्हे की तरह ही कार्य करते हैं।

हिप अर्थराइटिस को हराएं

जब कूल्हे के जोड़ में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए और कूल्हे की गतिविधि (मूवमेंट) में लगातार दिक्कत महसूस हो, तो इस स्थिति को सामान्य भाषा में कूल्हे (हिप) की अर्थराइटिस कहा जाता है।

देश में घुटने की अर्थराइटिस के मामले ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन संपन्न विकसित देशों में कूल्हे की अर्थराइटिस के मामले घुटने की अर्थराइटिस से कहीं ज्यादा सामने आते हैं। इसके बावजूद यह भी सच है कि देश में युवा वर्ग के लोग भी कूल्हे की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। जो युवक शराब का नियमित रूप से सेवन करते हैं, उनके कूल्हे की हड्डी में रक्त का संचार (सर्कुलेशन) कम होने लगता है और धीरे-धीरे कूल्हा कमजोर होने लगता है। इस समस्या को एवैस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है।

कारण

कूल्हे की अर्थराइटिस के लिए पांच कारण प्रमुख रूप से जिम्मदार हैं..

- एवैस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या।
- पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस(कूल्हे की हड्डी में चोट लगने के कारण)।
- एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण।
- यूमैटाइड अर्थराइटिस।
- टी.बी. के संक्रमण का दुष्प्रभाव।

लक्षण

- कूल्हे में दर्द का बरकरार रहना।
- चाल में लंगड़ाहट।
- पाल्थी मारने में विफल रहना।
- चलने फिरने की क्षमता का कम होना।

जांचे- एक्सरे और जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और एमआरआई।

इलाज - अगर पीड़ित व्यक्ति का मर्ज शुरुआती स्थिति में है, तो उसे दवाएं लेने, फिजियोथेरेपी कराने और आराम करने की सलाह दी जाती है। जब अन्य चिकित्सकीय उपचार विफल हो जाते हैं, तब कूल्हे का प्रत्यारोपण (हिप रिप्लेसमेंट) ही एकमात्र कारगर विकल्प होता है। ऐसा प्रत्यारोपण लगभग 100 फीसदी सुरक्षित है। नवीनतम तकनीकों से तैयार हुए कृत्रिम कूल्हे अब काफी हद तक कुदरती स्वस्थ कूल्हे की तरह कार्य करते हैं। प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकता है।

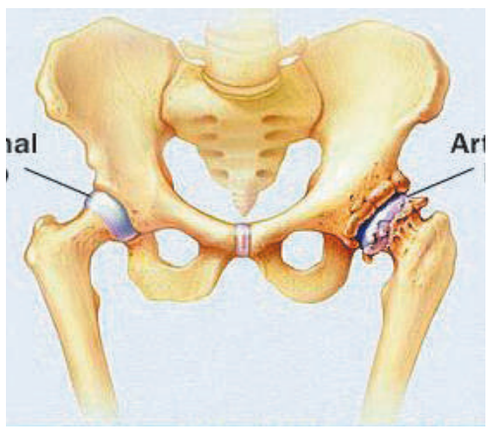

बच्चों और किशोरों में अर्थराइटिस

लगभग 6 महीने से 18 वर्ष तक के हर 250 बच्चों या किशोरों में से एक बच्चा या किशोर किसी न किसी प्रकार की गठिया (अर्थराइटिस)से पीड़ित है। बच्चों को प्रभावित करने वाली गठिया लगभग 16 प्रकार की होती है, परन्तु इनमें से मुख्य रूप से जुवेनाइल यूमैटॉइड अर्थराइटिस, यूमैटिक अर्थराइटिस,इंट्रो-अर्थराइटिस, एक्यूट ट्रांजिएंट अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस आदि मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित करते हैं। इलाज द्वारा इन रोगों पर इस हद तक काबू पाना कि वह बच्चे की पढ़ाई या रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा न बने अपने आप में एक चुनौती है।

जुवेनाइल यूमैटॉइड अर्थराइटिस

जुवेनाइल यूमैटॉइड अर्थराइटिस गठिया से प्रभावित लगभग 10 प्रतिशत बच्चों में पाया जाता है। हर 1000 बच्चों में से एक बच्चा इससे प्रभावित होता है। भारत में लगभग 15 लाख बच्चे इससे पीड़ित हैं। आम तौर पर यह अर्थराइटिस 16 वर्ष की आयु से पहले कभी भी हो सकता है। यह रोग शरीर के रोग-प्रतिरोधक तंत्र (इम्यून सिस्टम) में विकार आने से उत्पन्न होता है। लगभग 60 प्रतिशत प्रभावित बच्चों में इसका सीधा संबंध माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु से माना जाता है।

लक्षण

- एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द और सूजन का होना।
- बुखार आना।
- आंखों में सूजन और लालिमा का होना।
- उपर्युक्त लक्षण छह हफ्ते से लेकर तीन महीने तक कायम रह सकते हैं।
- रक्त में हीमोग्लोबिन का कम होना और व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा पायी जाती हैं।

इलाज- यदि जुवेनाइल यूमैटॉइड अर्थराइटिस का विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा समय से इलाज कराया जाए, तो जोड़ों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। ज्यादातर बच्चों को सूजन की दवाओं के अतिरिक्त डिजीज मॉडीफाइंग ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं।

यूमैटिक अर्थराइटिस- यूमैटिक अर्थराइटिस की शुरुआत गला खराब करने वाले स्ट्रेप्टोकोक्कॅल नामक जीवाणुओं द्वारा होती है। इसलिए इसे पोस्ट-स्ट्रेप्टोकोक्कॅल अर्थराइटिस भी कहते हैं। अक्सर यह अर्थराइटिस यूमैटिक फीवर के साथ शुरू होती है और कभी-कभी इससे हृदय भी प्रभावित होता है, जिसे यूमैटिक हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। इस रोग की जांचों में ए. एस. ओ. टाइटर का बढ़ा होना, ई. एस. आर. और सी. आर. पी. का बढ़ा होना पाया जाता है। इसमें 16 से 17 वर्ष की उम्र तक इलाज कराना पड़ता है।

बच्चों और किशोरों में तीसरे प्रकार की गठिया स्पॉन्डिलोआर्थो पैथी समूह से संबंधित है और यह भी शरीर के रोगप्रतिरोधक तंत्र (इम्यून सिस्टम) में विकार आने से उत्पन्न होती है। आम तौर पर इस प्रकार की गठिया (अर्थराइटिस) में मेरुदंड (स्पाइनल कॉर्ड) और हाथ व पैर के बड़े जोड़ प्रभावित होते हैं। इसमें भी विशेष प्रकार की इम्यूनो-मॉड्यूलेटर दवाओं की आवश्यकता होती है।

इस्कीमिक स्ट्रोक

लापरवाही बन सकती है जानलेवा

हाई ब्लडप्रेशर, मधुमेह (डाइबिटीज) के साथ अनियमित दिनचर्या और तनाव के कारण जीवन-शैली से संबंधित रोगों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे रोगों के बीच स्ट्रोक या ब्रेन अटैक शायद सबसे घातक है, लेकिन दुख की बात है कि लगातार इसके भयानक परिणाम बढ़ते जा रहे हैं।

इस्कीमिक स्ट्रोक की स्थिति

इस स्ट्रोक का अटैक रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण होता है। स्ट्रोक के कारण कुछ मस्तिष्क कोशिकाएं तुरंत ही मृत हो जाती हैं। स्ट्रोक के बाद मस्तिष्क का कुछ भाग ऐसा होता है, जो कार्य नहीं कर रहा होता है, लेकिन यह पूरी तरह से मृत भी नहीं होता है। इस स्थिति में यदि शीघ्र ही मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की जाए, तो मस्तिष्क के इस भाग को बचाकर मरीज की स्ट्रोक से रिकवरी संभव है।

लक्षण- ब्रेन अटैक के लक्षणों को अंग्रेजी शब्द- फास्ट से सरल रूप से समझा जा सकता है।

एफ- फेस ड्रूपिंग यानी चेहरे का एक तरफ से लटक जाना या सुन्न हो जाना।

ए- आर्म वीकनेस यानी हाथों में अचानक सुन्नपन। यदि व्यक्ति से दोनों हाथों को उठाने के लिए कहा जाएगा, तो उसका एक हाथ नीचे की तरफ झुका रहेगा।

एस - स्पीच डिफिकल्टी यानी बोलने या समझने में अचानक दिक्कत।

टी- टाइम यानी बिना देरी किए शीघ्र ऐसे अस्पताल पहुंचें, जहां पर स्ट्रोक का इलाज संभव हो।

फास्ट के अतिरिक्त वे लक्षण जिन्हें जानना जरूरी है- अचानक दोनों आंखों से स्पष्ट देखने में तकलीफ

होना। अचानक से चलने या बैलेंस करने में परेशानी। चक्कर आना। अचानक बिना कारण सिर में तेज दर्द होना।

उपचार- इस्कीमिक स्ट्रोक में उपचार के अंतर्गत एक छोटे ट्यूब (कैथेटर) को पैर की खून की नली (धमनी या आर्टरी) के मार्ग से मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। रक्त के जिस क्लॉट ने मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नली को अवरुद्ध किया होता है, उसे एक विशेष विधि से मस्तिष्क से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मस्तिष्क में रक्तसंचार सामान्य हो जाता है। इस कारण मरीज शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करता है।

निरोग रहने के लिए क्या करें

- सिर को गर्मी से, छाती को सर्दी से तथा आंखों को तेज हवा, धूल-मिट्टी, धुएं और तेज रोशनी से बचाकर रखें।
- कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों (कास्मैटिक्स, मेकअप) का प्रयोग न करें, क्योंकि ये त्वचा के रोमछिद्रों को बंद करके त्वचा को नुक्सान पहुंचाते हैं।
- मल, मूत्र, उल्टी, छींक, डकार, भूख, प्यास आदि वेगों को कभी न रोकें, क्योंकि इन्हें रोकने से रोग उत्पन्न होते हैं।
- गर्म भोजन करने के बाद, दूध पीने के बाद, खीरा, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी खाने के बाद, सो कर उठने के तुरंत बाद तथा अधिक शारीरिक परिश्रम के तुरंत बाद पानी न पिएं।
- मन में कामुक विचार न लाएं, कामुक चिंतन से बचें।
- हमेशा सभी के लिए मन में शुभ विचार रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें।
- हर परिस्थिति में शांत, सहज बने रहें, हमेशा प्रसन्नचित रहें।
- कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
- ज्यादा ऊंची हील वाले चप्पल-जूते न पहनें, ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
- हमेशा ढीले-ढाले वस्त्र पहनें,अत्यधिक तंग वस्त्र शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं।
- कड़े बिस्तर पर सोएं, बिस्तर अत्यधिक मुलायम और गद्देदार नहीं होना चाहिए।

प्राणघातक हो सकती है कैल्शियम की कमी

कैल्शियम को सदा से ही मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक माना जाता रहा है किन्तु नए शोधों के अनुसार इसके अतिरिक्त भी कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कई बीमारियों को दूर रखने में सहायता करता है। हड्डियां हमारे शरीर के लिए कैल्शियम के स्टोर का कार्य करती हैं जहां से आवश्यकतानुसार शरीर कैल्शियम लेता रहता है।

हमारे भोजन से हड्डियों को कैल्शियम मिलने और हड्डियों से शरीर को कैल्शियम मिलने की प्रक्रिया हेतु विटामिन 'डी' की उपस्थिति अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार हर वयस्क को न्यूनतम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की दैनिक आपूर्ति होनी आवश्यक है। यदि भोजन से इतना कैल्शियम नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर को पैराथायराइड हार्मोन विटामिन 'डी' के सहयोग से हड्डियों से रक्त का कैल्शियम स्थानांतरित कर देता है। यदि व्यक्ति के भोजन में लगातार कैल्शियम या विटामिन 'डी' की कमी चलती रहे तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। नवीन शोधों के अनुसार कैल्शियम की कमी का निम्न रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है।

उच्च रक्तचाप - मनुष्य के रक्तचाप पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। शरीर का वजन, शारीरिक गतिविधि, नमक व पारिवारिक पृष्ठभूमि का रक्तचाप पर प्रायः प्रभाव पड़ता है किन्तु अब शोधों से पता चला है कि शरीर में कैल्शियम की कमी से आयु के साथ रक्तचाप में भी प्रभाव पड़ता है।

1997 में अमरीका में पाया गया है कि कम वसा वाले दूध, फल और सब्जियों के नियमित प्रयोग से (जिसमें लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हो) रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। यह नहीं कि कैल्शियम के साथ नमक अधिक लिया जाए किन्तु अधिक नमक और कम कैल्शियम खाने वाले व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है।

डा. डेविड मैकरोन के अनुसार कम नमक वाले भोजन के स्थान पर दूध से बने पदार्थ उच्च रक्तचाप को काबू करने में अधिक प्रभावशाली हैं। उनके अनुसार अधिकतर बच्चे कैल्शियम की सही मात्रा नहीं लेते क्योंकि वे दूध, फल और सब्जी का सही मात्रा में सेवन नहीं करते।

कैंसर - हमारे शरीर में बहुत से सैल बनते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं । पेट के अंदर ऐसे सैल प्रायः 3 से 10 दिन में बदल जाते हैं पर कभी-कभी ये सैल तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं, जिससे पेट के कैंसर की संभावना हो सकती है। अमरीकन मैडीकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार जिन लोगों में पेट के कैंसर की संभावना थी, उन्हें 1500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन दिए जाने पर सैलों में बढ़ौतरी ठीक हो गई।

मासिक धर्म - प्रायः महिलाओं को मासिक धर्म प्रारंभ होने से पूर्व कई तकलीफें होती हैं। सूसन थाई जैकब के अनुसार इसके लिए भी कैल्शियम की कमी ही उत्तरदायी है। उन्होंने 466 महिलाओं को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन दिया और पाया कि अधिकतर महिलाओं की तकलीफें 48 प्रतिशत कम हो गईं। उनको होने वाली दर्द में भी कमी हुई।

यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आहार को इस प्रकार संयोजित करें कि हमें लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन मिलता रहे। 240 मिलीलीटर गाय के दूध में 288 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जबकि 200 ग्राम दही में 268 मिलीग्राम कैल्शियम होता है।100 ग्राम सूखे नारियल में 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जबकि 100 ग्राम खजूर में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त गूड़, पनीर, सोयाबीन, फूलगोभी और मछलियों में भी कैल्शियम पाया जाता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस- 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल जम्मू से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

गोरखा सैनिकों की वीरगाथा को संजोएगी योगी सरकार

गोरखपुर, 2 सितंबर। मां भारती की आन, बान व शान में सर्वस्व न्योछावर करने का जज्बा रखने वाले गोरखा सैनिकों की वीरगाथा को संजोने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके तहत प्रदेश का संस्कृति विभाग गोरखा रेजिमेंट के गोरखा भर्ती डिपो (जीआरडी) गोरखपुर में स्थित गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण कराने के साथ यहां एक भव्य संग्रहालय (म्यूजियम) बनवाने जा रहा है। इसका शिलान्यास 4 सितंबर (गुरुवार) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान के हाथों होने जा रहा है।

जनता पहली बार देख और जान सकेगी गोरखा रणबाकुरों की कहानी

उल्लेखनीय है कि आम जनता के अवलोकनार्थ बनने वाला यह गोरखा रेजिमेंट का पहला संग्रहालय होगा। इस तरह देश विदेश में अपने शौर्य से खास पहचान बनाने वाले गोरखा रणबाकुरों की कहानी से आम लोग पहली बार रूबरू हो सकेंगे। उस तरह का यह देश का पहला संग्रहालय होगा। गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश जलनिगम नगरीय की सीएंडडीएस यूनिट 42 का चयन किया गया है। स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय के निर्माण पर 44 करोड़ 73 लाख 37 हजार रुपये की लागत आएगी। इसके तहत संग्रहालय, टॉयलेट ब्लॉक, टिकट काउंटर, वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार, वाटर बॉडी, चहारदीवारी, लिफ्ट आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो, सेवन डी थिएटर, म्यूरल पेंटिंग आदि की व्यवस्थाएं भी रहेंगी। गोरखा सैनिक भारतीय सेना में अपने विशेष युद्ध कौशल के लिए विख्यात हैं। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक भारतीय सेना में गोरखा जवानों ने 2700 से अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गोरखा जवानों ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देश के आजाद होने के बाद गोरखा सैनिकों ने युद्ध के साथ ही शांति अभियानों में अतुलनीय भूमिका का निर्वहन किया है। वर्तमान समय में करीब 40000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में सेना चरण और अग्रिम क्षेत्र भ्रमण का शुभारंभ

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। जिसमे भारत के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घरानों के पत्रकार शामिल हैं, ने पाठ्यक्रम के सबसे कठिन, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक मॉड्यूल, सप्ताह भर चलने वाले भारतीय सेना चरण और अग्रिम क्षेत्र भ्रमण (एफएटी) का शुभारंभ 02 सितंबर 2025 को किया।

देश के सभी भागों से आए पत्रकार नोडल अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल धरन के नेतृत्व में 18 अगस्त 2025 को शुरू हुए डीसीसी के लिए कोच्चि में एकत्रित हुए थे। पाठ्यक्रम के प्रतिभागी कोच्चि में नौसेना चरण और बरेली में वायु सेना चरण के बाद, 01 से 06 सितंबर 2025 तक जम्मू क्षेत्र में भारतीय सेना चरण के लिए जम्मू पहुँचे।

आर्मी लेग की शुरुआत राइजिंग स्टार कॉर्प्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स की ओर से जम्मू के जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल के स्वागत भाषण से हुई। डीसीसी टीम ने रत्नुचक और कालूचक सैन्य स्टेशन का दौरा किया ताकि बख्तरबंद और तोपखाने के उपकरणों, प्रशिक्षण गतिविधियों, बाधा पार करने के अभ्यास और युद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने के लिए टैंक चलाने का अनुभव प्राप्त किया जा सके।

भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर आवाजाही फिर बाधित

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। बनिहाल और आसपास के सेक्टरों में मंगलवार को लगातार भारी बारिश से एक बार फिर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि सुरक्षा कारणों से वाहनों का यातायात अब तक निलंबित कर दिया गया है।

कई हिस्सों में मामूली भूस्खलन और पत्थर गिरने की खबरों ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग जो कई दिनों तक बंद रहने के बाद कल आंशिक रूप से बहाल किया गया था लगातार बारिश के कारण आज नहीं खोला जा सका। एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। भारी बारिश के कारण हम इस स्तर पर यातायात की अनुमति देने का जोखिम नहीं उठा सकते। अधिकारी ने यात्रियों को नवीनतम स्थिति की पुष्टि किए बिना मार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी। अधिकारी ने कहा कि हम लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक अपडेट की जांच करने का आग्रह करते हैं। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जारी की गई सलाह के अनुसार मुगल रोड पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। बता दें कि 250 किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से हर मौसम में जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है और बारिश और भूस्खलन के कारण बार-बार बंद होने से आवश्यक आपूर्ति बाधित होती है।

जम्मू नगर निगम ने भारी बारिश के बाद सघन सफाई और राहत अभियान शुरू किया

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। जम्मू शहर में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण अभूतपूर्व क्षति हुई है जिससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और निवासी परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश ने निचले इलाकों को खास तौर पर प्रभावित किया है जहाँ भारी गाद और मलबे के साथ पानी घरों में घुस गया है, जिससे भारी असुविधा हुई है और संपत्ति को नुकसान पहुँचा है।

जम्मू नगर निगम (जेएमसी) ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है बाढ़ प्रभावित इलाकों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए परिवहन अधिकारियों और सफाई अधिकारियों सहित नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें तैनात की हैं और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त मशीनरी को काम पर लगाया है। बहाली कार्यों के लिए जनशक्ति बढ़ाने हेतु मलबा सफाई और सफाई कार्यों के लिए आपातकालीन आधार पर 200 अतिरिक्त नाला मजदूरों को काम पर लगाया गया है। प्रभावित इलाकों से जमा कीचड़ और मलबे को हटाने के लिए युद्धस्तर पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मौजूदा मशीनरी के साथ-साथ, इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त मशीनें भी मँगवाई गईं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में पीर को, गोरख नगर, राजेंद्र नगर और गुज्जर नगर शामिल हैं जहाँ सामान्य जीवन स्तर बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम चल रहा है। गुज्जर नगर, राजेंद्र नगर और संग्रामपुर के कुछ इलाकों को साफ़ कर दिया गया है और अन्य इलाकों में तेज़ी से काम जारी है। तवी नदी के उफान ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं और बुनियादी ढाँचे और आवासीय परिसरों को भारी नुकसान पहुँचा है। इससे निपटने के लिए, जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने सभी विभागों को सफ़ाई प्रक्रिया में तेज़ी लाने आवश्यक सेवाएँ बहाल करने और निवासियों को तत्काल राहत प्रदान करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वह व्यक्तिगत रूप से घटनास्थलों का दौरा कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

जम्मू पुलिस ने नगरोटा उप-मंडल में गोवंश तस्करी की कोशिश नाकाम की

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत गोवंश तस्करों पर शिकंजा कसते हुए झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन की टीम ने गोवंश तस्करी के एक प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें कुल 10 गोवंश बचाए गए। झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन द्वारा 10 गोवंशों से भरा एक ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या जेके02एक्यू/0586 है ज़ब्त किया गया। ट्रक के चालक शाहजहाँ पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन निवासी पंजल्ला तह. रहमा जिला बारामूला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 111/2025 धारा 223 बीएनएस/11 पीसीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच जारी है।

पुलिस ने लापता महिला का पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिलवाया

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। पौनीचक पुलिस चौकी पर एक महिला (नाम गुप्त रखा गया है) निवासी जम्मू के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 21/08/2025 को पौनीचक पुलिस चौकी पर दर्ज की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक पौनीचक के नेतृत्व में पुलिस चौकी पौनीचक की एक पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत की और तकनीकी सहायता तथा मानवीय खुफिया जानकारी की मदद से लापता महिला का पता लगा लिया गया और सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उक्त महिला को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया। तदनुसार, गुमशुदगी की रिपोर्ट बंद कर दी गई है।

जावेद राणा ने पुंछ में पुनर्स्थापना प्रयासों की समीक्षा की

जम्मू 02 सितंबर। हाल ही में आई बाढ़ों के कारण पुंछ ज़िले में हुई व्यापक तबाही के बाद, जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय कार्य मंत्री, जावेद अहमद राणा ने एक विस्तृत वर्चुअल बैठक के माध्यम से राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मंत्री ने पुनर्स्थापना उपायों की प्रभावी योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया कि बहाली कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और विभागाध्यक्ष स्वयं ज़मीनी स्तर पर निगरानी करें ताकि कार्यों की गति तेज़ हो सके। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि विशेषकर दूर-दराज़ और संवेदनशील क्षेत्रों में प्राथमिक ध्यान पेयजल, बिजली, सड़क संपर्क, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने पर होना चाहिए। मंत्री ने प्रभावित परिवारों के लिए एक समग्र और समावेशी पुनर्वास रणनीति बनाने तथा भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक रोकथाम उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुआवज़ा और राहत सहायता शीघ्र और न्यायसंगत ढंग से दी जाए, खासतौर से उन परिवारों को जो सबसे अधिक प्रभावित और जोखिमग्रस्त हैं। शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को रेखांकित करते हुए, राणा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों का विस्तृत संरचनात्मक ऑडिट कराने पर बल दिया। उन्होंने विभागों को कमजोर स्कूल भवनों की पहचान करने, त्वरित मरम्मत करने और संस्थानों को छात्रों व स्टाफकी सुरक्षा हेतु दुरुस्त करने के निर्देश दिए। क्षति आकलन के तहत, उपायुक्त पुंछ, अशोक कुमार शर्मा ने मंत्री को जानकारी दी कि ज़िले में 18 विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीमा-दीवारों को नुक़सान पहुँचा है, जबकि 4 विद्यालयों की तत्काल मरम्मत आवश्यक है ताकि पढ़ाई सुरक्षित ढंग से जारी रह सके। इन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। सड़क अवसंरचना पर जानकारी देते हुए बताया गया कि मेंढर उपमंडल की 71 सड़कों में से 65 को वाहन योग्य बना दिया गया है, जबकि शेष पर कार्य जारी है। सुरनकोट उपमंडल में 10 सड़कों को नुक़सान पहुँचा है, जहाँ बहाली कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। अधिकांश पीएमजीएसवाई योजनांतर्गत सड़कें भी बहाल कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और सुरक्षा कार्यों की क्षति को देखते हुए मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को विशेष मामले के रूप में मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य सौंपने के निर्देश दिए, ताकि सबसे प्रभावित गाँवों में राहत व पुनर्वास तेज़ी से हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उपायुक्त ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। चिकित्सकीय पहुंच और मज़बूत करने हेतु मंत्री ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को मेंढर, सुरनकोट और हवेरी इलाक़ों में 10-10 दिन रोटेशन आधार पर तैनात करने का सुझाव दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को समय पर चिकित्सा मिल सके।

बिजली आपूर्ति की बहाली पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिजली बाधित होने से जलापूर्ति भी प्रभावित होती है क्योंकि अधिकांश जल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं।

लगातार बारिश से हो रहे नुकसान के बाद डीसी कठुआ ने सरकारी भवनों की सुरक्षा जाँच के दिए आदेश

कठुआ, 02 सितंबर (हि.स.)। जिला कठुआ में हाल ही में हुई भारी बारिश और बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान के खतरे को देखते हुए डीसी कठुआ ने जिले के सभी सरकारी भवनों की तत्काल सुरक्षा जाँच के निर्देश दिए हैं।

इस आदेश में स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, कॉलेज भवन, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग में लाने से पहले ये ढाँचे सुरक्षित हैं।

आदेश के अनुसार सभी जिला प्रमुखों को ऐसी इमारतों के संचालन से पहले सुरक्षा जाँच की निगरानी करनी होगी। शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों (जेडईओ) के साथ समन्वय में, कक्षाएं फिर से शुरू करने से पहले सुरक्षा जाँच पूरी करने का निर्देश दिया गया है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी स्कूलों के लिए इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिले के सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भवनों की जाँच सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा गया है। इस पहल का उद्देश्य बारिश से होने वाले संरचनात्मक नुकसान से उत्पन्न होने वाले खतरों को रोककर छात्रों, कर्मचारियों और आम जनता के जीवन की रक्षा करना है। उपायुक्त ने सभी संबंधितों के कल्याण के लिए आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने पर बल दिया है।

शोपियां के गणोवपोरा में मछली फार्म में 3500 मछलियां मृत पाई गईं

जम्मू, 2 सितंबर (हि.स.)। शोपियां के गणोवपोरा गांव में एक निजी मछली फार्म में लगभग 3,500 मछलियां मृत पाई गईं। स्थानीय युवाओं द्वारा स्थापित इस फार्म को कथित रूप से किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ डालकर नुकसान पहुँचाया।

फार्म चार साल पहले बिलाल अहमद ने शुरू किया था, जिन्होंने इसे स्थापित करने में कड़ी मेहनत की थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से बिलाल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, खासकर तब जब उनकी बहन की शादी मात्र पांच दिन बाद होनी थी।

स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है और जांच की जा रही है।

सकीना इत्तू द्वारा जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी-2025 की तैयारी हेतु प्रक्रियाओं की समीक्षा

श्रीनगर 02 सितंबर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी-2025 के मसौदे की तैयारी संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। यह ऐतिहासिक नीति-जांच ढाँचा जम्मू-कश्मीर में उच्च शिक्षा के अवसरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु, विशेष सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मंत्री ने व्यापक विचार-विमर्श किया और कहा कि नीति का मसौदा प्रगतिशील एवं व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग को मजबूत नियामक ढाँचे के साथ संतुलित किया जा सके।

मंत्री ने ज़ोर दिया कि यह नीति प्रतिष्ठित निजी संस्थानों के लिए जम्मू-कश्मीर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सक्षम वातावरण तैयार करे, साथ ही शैक्षणिक ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को उन्नत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और स्थानीय छात्रों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीति का मसौदा सभी हितधारकों, छात्रों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही तैयार किया जाए। साथ ही इसमें राजस्व, उद्योग एवं वाणिज्य, वित्त सहित विभिन्न विभागों से परामर्श लेकर आवश्यक सुझावों को शामिल किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि स्पष्ट एवं पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार कर उन्हें सार्वजनिक परामर्श हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए और प्रासंगिक सुझावों को शामिल कर आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ। सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी-2025 एक दिशा-निर्देशकारी ढाँचे के रूप में कार्य करेगी, जो विश्वसनीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी और जम्मू-कश्मीर को देश व विदेश में ज्ञान, नवाचार और कौशल विकास का नया केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER JAL SHAKTI
MECH. G.W.D. DIVISION JAMMU
SHORT TERM NOTICE INVITING e-TENDER

E -NIT NO GWD/77 OF 2025-26 DATED 30.08.2025

On behalf of the Lt. Governor, UT of J&K, the Executive Engineer Jal Shakti Mech. Ground Water Drilling Division Jammu invites tenders by e-tendering mode from reputed and registered firms with Jal Shakti PHE/I&FC Deptt. J&K Govt. who have sufficient experience in the field of drilling and are well equipped with drilling Rigs suitable for ODEX method of drilling.

Name of the Work	Name of the Division	Cost of Tender Document/Tender Fee (In Rs)	Qty.	Estimated cost (value of work) (in Rs.)	Earnest Money (In Rs)	Validity of Rates
Deep Drilling of 125 mm dia Bore Holes by using ODEX method including providing, installation, testing, commissioning of Mark-II Hand Pumps at (03 Nos) different locations in District Samba on Turnkey Basis (EPC) under District Capex Budget (2025-26)	Jal Shakti Mech. Ground Water Drilling Division Jammu	1000.00 (Non-Refundable) Deposited in Govt. treasury through e-challan under the receipt head 0215 in favour of the Executive Engineer, Jal Shakti Mech. GWD Div. Jammu payable at Jammu mentioning name of work	03 Nos	Rs. 8.30 lacs	@ 2% of the estimated value in shape of Fresh CDR/FDR pledged to Executive Engineer PHE (M) GWD Division	31st March 2026

1. The complete bidding process shall be online.
2. Bid documents can be seen and downloaded from the website http://jktenders.gov.in from 30.08.2025 to 11.09.2025.
3. The pre bid meeting if desired by the participating firms shall be held in the office of the Executive Engineer Jal Shakti (M) GWD Division Jammu on 01.09.2025 (1300 hrs).
4. The bids shall be submitted/uploaded from the website http://jktenders.gov.in from 02.09.2025 (1400 hrs) to 11.09.2025 (1800 hrs).

GWD/3558-60 DATED: 30.08.2025

Sd/-
Executive Engineer
Jal Shakti Mech. G.W.D. Division
Jammu

DIP/J-5297/25
Dtd: 2-9-2025

संपादकीय

भ्रष्टाचार समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास जारी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश में सत्तासीन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के अभिशाप से निपटने के लिए सीमाएँ खींच दी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि रिश्वत लेना-देना अभी भी प्रचलन में है, हालाँकि भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियाँ इस सर्वव्यापी समस्या को क्षेत्र से खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को भ्रष्ट तत्वों पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार की समस्या इतनी विकराल है कि भ्रष्टाचार निरोधक उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों, खासकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पकड़े गए मामलों से यह तो पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या इस समस्या की भयावहता और गंभीरता को दर्शाती है क्योंकि लगभग हर अगले दिन कोई न कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने या लेने के आरोप में पकड़ा जाता है। इस संदर्भ में, ताज़ा मामला शोपियाँ से सामने आया है जहाँ एसीबी ने ग्रामीण विकास विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को 20,000 रुपये की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, यह ज़रूरी हो गया है कि सत्ताधारी लोग जम्मू-कश्मीर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपायों की दिशा बदलें, अन्यथा यह विकास और प्रगति के अन्य साधनों में बाधा बनता रहेगा। इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो इस परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। हालाँकि कभी-कभी लोगों को कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा उनके मोबाइल फोन पर संदेश मिलते हैं कि अगर कोई काम के बदले रिश्वत या अनुचित लाभ माँगता है तो पुलिस या सीबीआई को सूचित करें, लेकिन यह अपर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी लोग इसे रोकने के तरीकों पर चर्चा करें और ऐसा माहौल बनाएँ जहाँ पद पर आसीन लोग जनता के विरोध के डर से रिश्वत न माँग सकें।

जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, भ्रष्टाचार से लड़ना मुश्किल है क्योंकि यह समस्या गहरी जड़ें जमा चुकी है और अपराधी लोगों के काम के बदले अनुचित लाभ उठाने के नए-नए तरीके खोज लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार वेतन के रूप में भुगतान करती है।

जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और शून्य सहनशीलता संस्थानों और सार्वजनिक जीवन में आदर्श नहीं बन जाती, तब तक भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर का सपना दूर ही रहेगा। जब तक हर नागरिक इस दुष्चक्र का हिस्सा बनने से इनकार नहीं करेगा, तभी केंद्र शासित प्रदेश सही मायने में स्वच्छ शासन और सतत प्रगति की ओर बढ़ पाएगा।

बीत चुका है, हिमालय को सुनने का समय

हिमालय एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग% के अनुसार, इस क्षेत्र में संभवत- ग्लेशियर झील के फटने से भारी विनाश हुआ है और इसका मूल कारण %ग्लोबल वार्मिंग% और जलवायु-परिवर्तन है। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, अत्यधिक ठंड, बेकाबू बारिश जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल हैं। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और झीलें अस्थिर हो रही हैं।हिमालय एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। सन् 2012 में केंद्र सरकार ने भागीरथी नदी के गौमुख से उत्तरकाशी जलग्रहण क्षेत्र को एक पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य प्राचीन क्षेत्रों का संरक्षण और बुनियादी ढांचागत गतिविधियों का नियमन करना था, परन्तु केंद्र और राज्य सरकारें इन नियमों को लागू करने में ढिलाई बरतती रहीं।भारतीय मौसम विभाग% की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में औसत बर्फबारी में पिछले 50 वर्षों में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1962 से अब तक हिमालयी ग्लेशियरों का 30 प्रतिशत हिस्सा पिघल चुका है जिसकी वजह से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। सन् 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़, 2021 में जोशीमठ में ज़मीन और इमारतों के धंसकने, सन् 2023 में तीस्ता घाटी में हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ और हिमाचल प्रदेश में बार-बार आने वाले मानसूनी भूस्खलन और बाढ़ को वैज्ञानिक पारिस्थितिक और भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में असंतुलित बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम बताते हैं।आपदा प्रबंधन विभाग% और विश्वबैंक ने वर्ष 2018 में एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के अनुसार राज्य में 6300 से अधिक स्थान भूस्खलन जोन के रूप में चिन्हित किए गए थे। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में चल रही हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं पहाड़ों को काटकर या फिर जंगलों को उजाड़कर बन रही हैं और इसी कारण भूस्खलन जोन की संख्या बढ़ रही है। हिमालय न केवल हर साल बढ़ रहा है, बल्कि इसमें भूगर्भीय उठापटक चलती रहती है।पेड़ भूमि को बांधकर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं जो कि कटाव व पहाड़ को ढहने से रोकने का एकमात्र उपाय है। पहाड़ पर तोड़-फोड़ या धमाके होना या फिर उसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ का ही दुष्परिणाम है कि हिमालय में निरंतर भूकंप आते रहते हैं। जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंग या अविरल धारा को रोकने से पहाड़ अपने नैसर्गिक स्वरूप में नहीं रह पाता और उसके दूरगामी परिणाम विभिन्न प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आते हैं।सन् 2020 में चार धाम राजमार्ग के निर्माण की जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि संवेदनशील ढलानों से छेड़छाड़ न की जाए, परन्तु उसके विपरीत कार्य हो रहा है। हिमालय में बढ़ते पर्यटन के कारण होटल, मकान, सड़क, राजमार्ग आदि के निर्माण का भारी दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। जून 2022 में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थानद्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमा लय में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर दबाव बढ़ा है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय% द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में 1989 में 4.7 फीसदी क्षेत्र में भवन, होटल, सड़क, दुकान आदि का निर्माण हुआ था जो 2012 में 15.7 फीसदी हो गया और आज यह आंकड़ा 25 फीसदी से ज्यादा हो गया है। वर्ष 1980 से 2023 के बीच पर्यटकों की संख्या में 5600 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक विगत दो वर्षों से शिमला में आने वाले वाहनों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ गई है। शहर में सिर्फ 6000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन सीजन टाइम में प्रतिदिन 20,000 वाहन आते हैं।इन मानव-जनित चुनौतियों के चलते भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं विनाशकारी बनती जा रही हैं। हिमालयी क्षेत्र में, विशेषकर उच्च हिमालय की छोटी नदियों की घाटियों में, कई ऐसे स्थान हैं जहां विनाशकारी घटनाओं की संभावना बहुत अधिक होती है। ये घटनाएं अचानक घटित होती हैं। ऐसे स्थानों पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली काम नहीं आती। पहले इंसान ऐसे स्थानों पर बसते नहीं थे, लेकिन हाल के वर्षों में हमने इन स्थानों की संवेदनशीलता पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में सबसे अच्छा समाधान है, वहां रहने वाले लोगों को शिक्षित करना या बड़े पैमाने पर बस्तियां बसाने से रोकने के लिए कानून बनाना।भारतीय मौसम विज्ञान विभागके अनुसार, इस क्षेत्र में संभवत- ग्लेशियर झील के फटने से भारी विनाश हुआ है और इसका मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु-परिवर्तन है। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, अत्यधिक ठंड, बेकाबू बारिश जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल हैं। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और झीलें अस्थिर हो रही हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान% (आईआईएससी) की एक टीम को संदेह है कि खीरगंगा चैनल को पानी देने वाले एक %लटकते ग्लेशियरज् ने 5 अगस्त को धराली में आई विनाशकारी बाढ़ में भूमिका निभाई होगी।

कश्मीर, लद्दाख़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 28043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का बड़ा कारण बन सकती हैं। इससे लगभग तीन करोड़ की आबादी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इन ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली झीलें केवल एक पारिस्थितिक संकट नहीं हैं। इन झीलों से निकलने वाले पानी के कारण नदियों का बहाव प्रभावित होता है। इसके साथ ही, जिन झीलों का पानी पूरी तरह भर जाता है या जिनका किनारा टूटता है, वे नीचे बसे क्षेत्रों के लिए भारी तबाही का कारण बनती हैं।हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए सतत विकास और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा, ताकि हिमालय का संरक्षण किया जा सके और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी सुनिश्चित किया जा सके। पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, देहरादून के पूर्व निदेशक रवि चोपड़ा बताते हैं कि तेज़ आर्थिक विकास की कल्पनाओं से मोहित भारतीय नागरिकों के लिए जलवायु परिवर्तन की चेतावनी के प्रति सचेत होने और सुरक्षित, टिकाऊ और समतापूर्ण आर्थिक विकास की मांग करने का समय बहुत पहले बीत चुका है। प्रकृति की सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना ही हमारे अस्तित्व और आर्थिक विकास का सबसे सुरक्षित और तार्किक मार्ग है।

जैव विविधता से जैव-प्रौद्योगिकी तक: विकसित भारत की नई पहचान

- डॉ. निवेदिता शर्मा

भारत अब केवल अपनी जैव विविधता की धरोहर पर गर्व करने वाला देश नहीं रह गया है, उसने उस धरोहर को विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदलना शुरू कर दिया है। देश में जैव प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन रही है। पर्यावरणीय संतुलन, रोजगार सृजन और सामरिक स्वतंत्रता का भी प्रमुख आधार बनती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बायोई3 नीति के अंतर्गत उच्च-निष्पादन वाले जैव-विनिर्माण प्लेटफार्मों का शुभारंभ किया। एक नजरिए से देखें तो यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि भारत 21वीं सदी में केवल सूचना प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, यह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनने का इरादा रखता है। समीक्षात्मक रूप से देखें तो दुनिया के कई देशों के बीच भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जैव विविधता है। यह विश्व के 17 मेगाडायवर्स देशों में शामिल है। यहां लगभग पैंतालीस हजार से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और नब्बे हजार से अधिक पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हिमालय की जड़ी-बूटियों से लेकर अंडमान-निकोबार के समुद्री संसाधनों तक, यह जैव संपदा बायोटेक्नोलॉजी के लिए अमूल्य स्रोत है। यही कारण है कि कृषि, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण और समुद्री अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। परंपरागत आयुर्वेद और औषधीय पौधों का ज्ञान आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य समाधान प्रस्तुत कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति पिछले एक दशक में असाधारण रही है। 2014 में देश की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग दस अरब डॉलर के आसपास थी। 2023 तक यह बढ़कर डेढ़ सौ अरब डॉलर तक पहुंच गई और मार्च 2025 तक इसका आकार लगभग एक सौ पैंसठ अरब डॉलर हो गया। यह अब भारत की जीडीपी में चार प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है और पिछले चार वर्षों में औसतन अठारह प्रतिशत की दर से बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे तीन सौ अरब डॉलर तक ले जाया जाए। यह लक्ष्य अब अवास्तविक नहीं लगता क्योंकि बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या ही गवाही दे रही है। जहां 2014 में इनकी संख्या मात्र पचास थी, वहीं 2024 तक यह बढ़कर दस हजार से अधिक और 2025 में ग्यारह हजार तक पहुँच गई। इन स्टार्टअप्स को देश भर में सौ से अधिक इनक्यूबेटर और बीआईआरएसी जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। इस सब के सार्थक परिणाम यह है कि भारत अब वैश्विक मानचित्र पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। विश्व की 121 प्रमुख जैव कंपनियों में से 21 भारत में स्थित हैं। यह उपलब्धि उस देश के लिए विशेष महत्व रखती है जिसे कभी तकनीकी अनुसरणकर्ता माना जाता था। हैदराबाद का नाम दुनिया के सात सबसे बड़े लाइफ-साइंसेज क्लस्टर्स में शामिल हो चुका है जहां पचपन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है और दो लाख से अधिक नए रोजगार बने हैं। कर्नाटक राज्य ने अकेले ही तीस अरब डॉलर का बायो-आर्थिक योगदान दिया है और निकट भविष्य में तीस हज़ार अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। असम पहला राज्य है जिसने बायोई3 पहल को पूरी तरह से अपनाया है और पूर्वोत्तर को जैव प्रौद्योगिकी का नया केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहां समझ लीजिए कि बायोई3 नीति का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्मार्ट प्रोटीन, टिकाऊ कृषि, कार्बन कैप्चर, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और कोशिका एवं जीन थेरेपी जैसे क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि भारत को आयात पर निर्भरता से भी मुक्त करेंगे। पेट्रोलियम आयात को घटाने के लिए ईथेनॉल मिश्रण का प्रयास इसका उदाहरण है। 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण मात्र डेढ़ प्रतिशत था जो 2024 में पंद्रह प्रतिशत तक पहुँच गया। इसके कारण लगभग सत्रह मिलियन टन कच्चे तेल के आयात से बचाव हुआ और करीब एक लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस साल के अंत के बाद जो आंकड़े आएंगे, उम्मीद है कि यह पंद्रह प्रतिशत से बढ़कर ही आएंगे। जैव प्रौद्योगिकी का महत्व कोविड-19 महामारी के दौरान और भी स्पष्ट हो गया जब भारत ने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन विकसित कर पूरी दुनिया को आपूर्ति की। जिन देशों ने समय पर वैक्सीन प्राप्त की, उनमें भारत की भूमिका निर्णायक रही। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जैव प्रौद्योगिकी आज विज्ञान से आगे भू-राजनीतिक शक्ति का भी स्रोत बन चुका है। फिर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। अभी भी वेक्टर और प्लास्मिड जैसे आवश्यक बायोलॉजिकल इनपुट्स का उत्पादन देश में सीमित है। प्रोबायोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नियामकीय बाधाएँ उद्यमियों को परेशान करती हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए निजी निवेश और विदेशी सहयोग को और बढ़ाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के सामने बड़ा अवसर है परंतु चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए लागत और नीति में लचीलापन आवश्यक होगा।

राहुल की यात्रा का पहला दौर कामयाब : मगर असली लक्ष्य है बिहार जीतना

राहुल की बिहार यात्रा का पहला दौर खतम हो गया। दूसरा दौर जब भी शुरू हो मगर उससे पहले ही वोट चोरी पूरे देश में मुद्दा बन गई

अब विपक्ष को जो वहां महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहा है अपना पूरा ध्यान चुनाव की तैयारी पर लगाना चाहिए। चुनाव आयोग के दांव पेंच चलेंगे। उस पर दबाव पड़ा है। मगर मोदी सरकार की तरफ से दबाव ज्यादा है। जाहिर है कि सत्ता का दबाव ज्यादा काम करेगा बनिस्बत विपक्ष और जनता के दबाव के। लेकिन चुनाव आयोग की साजिशों के बावजूद महागठबंधन को अपना चुनाव पूरी ताकत और कुशलता से लड़ना होगा।वैराहुल की बिहार यात्रा का पहला दौर खतम हो गया। दूसरा दौर जब भी शुरू हो मगर उससे पहले ही वोट चोरी पूरे देश में मुद्दा बन गई। यही इस यात्रा का पहला उद्देश्य था। देश में जगह-जगह वोट चोरी पर चर्चा होने लगी। बिहार का आदमी देश में हर जगह है। वह बता रहा है कि उसके घर गांव में कितने वोट कटे। जो जिन्दा हैं उनके नाम मुर्दों में लिख दिए और जो कई-कई बार वोट डाल चुके हैं उनके नाम ही गायब हैं। 18, 20, 22 साल के युवा जिनका नाम खोज-खोज कर घर-घर जाकर पहले जोड़े जाते थे उनके नाम ही नहीं हैं।जागरुकता हर जगह फैल गई है। अब बंगाल में जहां इसके बाद एसआईआर करने का भाजपा सोच रही थी करना मुश्किल होगा। राहुल का यह प्राथमिक उद्देश्य था जो पूरा हो गया। मगर असली उद्देश्य या लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। अगर राहुल की इतनी सफल यात्रा जिसमें जनता ने सहभागिता के सारे रिकार्ड तोड़ दिए बिहार जीत में नहीं बदलती है तो यात्रा बेकार हो जाएगी। इसका उठाया मुद्दा वोट चोरी दम तोड़ देगा।अब विपक्ष को जो वहां महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहा है अपना पूरा ध्यान चुनाव की तैयारी पर लगाना चाहिए। चुनाव आयोग के दांव पेंच चलेंगे। उस पर दबाव पड़ा है। मगर मोदी सरकार की तरफ से दबाव ज्यादा है। जाहिर है कि सत्ता का दबाव ज्यादा काम करेगा बनिस्बत विपक्ष और जनता के दबाव के।लेकिन चुनाव आयोग की साजिशों के बावजूद महागठबंधन को अपना चुनाव पूरी ताकत और कुशलता से लड़ना होगा। निगाह चुनाव आयोग की धांधलियों पर रखना होगी। सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी करते रहना होगी। जनता को लगातार जागरूक करते रहना होगा और कार्यकर्ताओं को मजबूत करके बूथ लेवल तक पहुंचाना होगा।

आखिरी मैसेज चुनाव नतीजों से ही जाएगा। लड़ाई बराबरी की नहीं है। विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मगर जब तक मोदी है विपक्ष के पास कोई आप्शन नहीं है। इन्हीं हालातों में लड़ना होगा।पहले तो यह था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनाव के जरिए ही हटाया जा सकेगा। मगर पहलगाम के आतंकवादी हमले और उसके बाद अमेरिका के दबाव में सीज फायर ने परिस्थितियां पूरी तरह बदल दी हैं। अभी संसद के खतम हुए मानसून सत्र में मोदी का गिरता हुआ असर साफ दिख रहा था। भाजपा सांसद उस तरह मोदी और अमित शाह के साथ खड़े नहीं दिखे जैसे इससे पहले के सत्रों में दिखते थे। लोकसभा जहां पिछले 11 साल में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया।विपक्ष के हर नेता को हूट किया गया। पूरे विपक्ष को सदन से निष्कासित कर दिया गया वहां मोदी के प्रवेश करने पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। अमित शाह के मुंह पर संविधान संशोधन का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाने का बिल फाड़कर फेंका गया।यह मोदी अमित शाह के डर के खतम हो जाने का परिचायक था। राहुल का पिछले कुछ समय से यही प्रमुख नारा था डरो मत! और डर विपक्ष में खतम हुआ लेकिन इसके साथ सत्ता पक्ष में भी बना डर का माहौल खतम हुआ।

मोदी के 11 साल के शासन का अगर कोई एक आधार था तो वह डर ही था। जिसकी वजह से खुद उनकी पार्टी, सभी संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया सब उनके नियंत्रण में रहते थे। अब वह डर खतम हुआ तो मोदी अपने आप कमजोर दिखने लगे। इसलिए जो पहले माना जाता था कि उन्हें केवल चुनाव के जरिए ही हटाया जा सकता है अब माना जाने लगा है कि खुद उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर से लेकर देश में हर जगह उनकी असफलताएं दिखने लगी हैं।राजनीति में नेता तभी तक स्वीकार्य होता है जब तक वह मजबूत दिखता है। राहुल गांधी का उनकी खुद की पार्टी में विरोध हो गया था। उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। मगर राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर दूसरी यात्रा करके और विपक्ष में एकजुटता लाकर इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को 2024 के चुनाव में बहुमत लाने से रोक दिया। उसके बाद राहुल न केवल अपनी पार्टी में पूरे विपक्ष में और जनता में मजबूत नेता के तौर स्थापित हो गए।और दूसरी तरफ उसी काल खंड में मोदी लोकसभा में बहुमत से दूर रहकर, अमेरिका के दबाव में आकर भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ सफलता के निर्णायक क्षणों में रोकने और उसके बाद भी टैरिफ को नहीं रोक पाने के बाद अपना सारा रौब रुतबा खो चुके हैं। बची खुची कसर उनकी चीन यात्रा ने पूरी कर दी।

गलवान में मारे गए हमारे बीस बहादुर सैनिकों की शहादत आंखों के सामने घूम गई। उसके बाद चीन को जो क्लीन चिट दी थी कि न कोई घुसा है न कोई है कि याद आ गई। चीन जाने की जरूरत पर सवाल होने लगे। जो चीन पाकिस्तान के साथ संघर्ष में पूरी तरह उसके साथ खड़ा था। हमारी सेना के उपसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि सामने पाकिस्तान था मगर पीछे चीन लड़ रहा था। अब पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है और चीन तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए। तुर्किए जिस तीसरे देश का नाम सेना ने लिया था कि वह भी पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था उससे फिर कारोबार शुरू कर दिया। गोदी मीडिया तक ने हेडिंग लगा दी रकार का यूटर्न। विदेश नीति पूरी तरह असफल बताई जा रही है।समस्या यह है कि विदेश नीति देश के लिए होती है। मगर मोदी पिछले 11 साल में अपनी छवि बनाने के लिए विदेश नीति चला रहे थे। अभी लेटेस्ट जापान का उदाहरण सामने है। वहां भारत जापान संबंधों में पलीता लगाकर गोदी मीडिया यह दिखा रहा है कि जापान में भारतीय सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मोदी की वजह से कोई डर नहीं है। यह जापान पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। वहां भारतीय या विदेशी सुरक्षित नहीं। कोई देश कैसे बर्दाश्त करेगा?मोदी का नाम रहे। बाकी देश के बारे में लोग क्या सोचेंगे इसकी चिन्ता नहीं। हर देश में जहां मोदी जाते हैं ऐसे ही ड्रामे किए जाते हैं। और इसी का असर है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ।

यही हालत अब भाजपा के अंदर सवाल पैदा कर रहे हैं। संघ ने अभी उसके सौ साल का जश्न नहीं बिगड़े इसलिए 75 साल की उम्र के मसले को किनारे कर दिया है। मगर इससे सवाल खत्म नहीं होगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत मोदी के साथ डूबती नाव का सफर नहीं करेंगे। फिलहाल भाजपा और संघ दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि सवाल कहां से उठेंगे। कहीं से भी उठ सकते हैं।

भारत में होगा 2026 बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, नई दिल्ली बनेगा मेज़बान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत को एक बार फिर बैडमिंटन की दुनिया में बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका ऐलान पेरिस में चल रही मौजूदा विश्व चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान किया गया। इस मौके पर भारत के स्टार डबल्स जोड़ीदार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कांस्य पदक जीता, जो उनकी विश्व चैंपियनशिप में दूसरी पदक उपलब्धि है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा, हम बीडब्ल्यूएफ का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारत को यह मेज़बानी सौंपी। हम भरोसा दिलाते हैं कि भारत भी पेरिस की तरह उत्कृष्टता और भव्यता के उसी स्तर को आगे बढ़ाएगा। हम पूरी बैडमिंटन फैमिली का दिल्ली में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

भारत का विश्व चैंपियनशिप में प्रदर्शन

अब तक भारत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 15 पदक जीते हैं। इनमें से पांच पदक अकेले पीवी सिंधु ने जीते हैं– 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य।ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने 2 कांस्य पदक हासिल किए। किदांबी श्रीकांत ने 2021 में रजत जीता, जबकि साई प्रणीत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय ने हाल के वर्षों में कांस्य पदक दिलाए।

पीकेएल-12 : पुनेरी पल्टन की धमाकेदार जीत, गुजरात पर 41-19 की बड़ी बढ़त

विशाखापट्टनम। प्रो कबड्डी लीग (सीजन 12) के आठवें मैच में पुनेरी पल्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात जाएंट्स को 41-19 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पल्टन ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और गुजरात को दो बार आलआउट किया। इस जीत के साथ पल्टन ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि गुजरात को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। पुनेरी पल्टन की जीत में डिफेंस की बड़ी भूमिका रही। टीम ने डिफेंस से 18 अंक बटोरे जबकि गुजरात को सिर्फ सात अंक मिले। अबिनेश नादराजन ने अकेले छह अंक लेकर हाई-5 पूरा किया, जबकि गुरदीप और गौरव ने चार-चार अंक जुटाए। रेड में आदित्य (6 अंक) और पंकज मोहिते (5 अंक) ने शानदार खेल दिखाया। गुजरात के लिए केवल एचएस राकेश (6 अंक) ही कुछ खास कर पाए। मैच की शुरुआत में गुजरात ने सुपर टैकल से पलटवार करने की कोशिश की और स्कोर 5-5 कर लिया। लेकिन पल्टन ने शानदार वापसी करते हुए पहला आलआउट कराया और 12-6 की लीड हासिल की। हाफटाइम तक पल्टन 17-11 से आगे थी। इस दौरान डिफेंस में पल्टन के खिलाड़ियों ने लगातार दबदबा बनाए रखा।

पीकेएल-12: यूपी योद्धाज की रोमांचक जीत, 8 अंकों के घाटे से वापसी कर पटना पाइरेट्स को हराया

विशाखापट्टनम। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन-12 के सातवें मुकाबले में यूपी योद्धाज ने तीन बार की चैंपियन टीम पटना पाइरेट्स को 34-31 से मात दी। यह मुकाबला विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला गया। खास बात यह रही कि यूपी की टीम एक समय 8 अंकों से पीछे थी, लेकिन बेहतरीन खेल दिखाते हुए उसने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर के साथ हुई। यूपी के कप्तान सुमित ने शुरुआती अंक दिलाए, लेकिन पटना के अयान के मल्टीपॉइंटर रेड और मजबूत डिफेंस ने यूपी को पीछे धकेल दिया। पहले हाफ तक स्कोर 19-13 से पटना के पक्ष में था। ब्रेक के बाद यूपी ने रणनीति बदली और सुपर टैकल में आशू ने अयान को लपकते हुए टीम को गति दी। इसके बाद सुमित और भवानी के शानदार टैकल्स ने पटना को ऑलआउट कर यूपी को 26-25 से बढ़त दिला दी। आखिरी पलों में गगन के मल्टीपॉइंटर रेड और सुमित के निर्णायक टैकल ने यूपी की जीत सुनिश्चित कर दी।

जनपद स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर

मुरादाबाद। जनपद स्तरीय ताइक्वांडो बालक वर्ग की प्रतियोगिता पीएलजेएल रस्तोगी इंटर कॉलेज तथा बालिका वर्ग की प्रभादेवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में सम्पन्न हुई। पीएलजेएल रस्तोगी इंटर कॉलेज मुरादाबाद में प्रतियोगिता का उद्घाटन कालेज के प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार ने तथा प्रभादेवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्या शशि आर्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। महेंद्र कुमार व शशि आर्य ने खिलाड़ियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। बच्चे खेल के माध्यम से अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय का नाम ऊंचा करते हैं। दोनों प्रतियोगिताओं में पीएलजेएल रस्तोगी इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज, पारकर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, डी एस एम इंटर कॉलेज, प्रभादेवी इंटर कॉलेज, मैथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, साहू रमेश इंटर कॉलेज की छात्र एवं छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में जनपदीय एवं मंडलीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर तथा चयनकर्ता के रूप में मनोज कुमार, दीपक चंद्र, अर्जुन सिंह, उर्वशी गुप्ता, सरिता, संगीता चौधरी का प्रमुख सहयोग रहा।

प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झांसी ने मेरठ को 3-0 से हराया

एजेंसी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लालपुर स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल में खेले गए प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झांसी के खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में मेरठ की टीम को 3-0 से हरा दिया। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी ने पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। संकुल लालपुर के हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर 30 अगस्त से चार सितम्बर के बीच चल रहे प्रतियोगिता में तीसरे दिन दूसरा मुकाबला वाराणसी बनाम मिर्जापुर के मध्य हुआ। जिसमें वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिर्जापुर पर 8- 0 से जीत दर्ज की। यह जानकारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि

तीसरा मुकाबला चित्रकूट बनाम कानपुर के मध्य खेला गया। जिसमें दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे पर आक्रमण प्रति आक्रमण करते रहे। मैच में कानपुर की टीम ने 4- 3 से जीत दर्ज की। चौथा मुकाबला देवीपाटन बनाम अलीगढ़ के मध्य खेला गया। जिसमें देवीपाटन के खिलाड़ियों ने अलीगढ़ की टीम पर दबाव बनाकर खेलते हुए 6-1 से विजय हासिल की। इसी क्रम में पांचवा मुकाबला प्रयागराज बनाम मेरठ मंडल के मध्य खेला गया। जिसमें प्रयागराज की टीम 1-0 से जीत की। इसी क्रम में छठा मुकाबला झांसी बनाम गोरखपुर के मध्य खेला गया। जिसमें झांसी की टीम ने गोरखपुर को 4-3 से पराजित कर दिया। सातवां मुकाबला वाराणसी बनाम देवीपाटन मंडल के मध्य खेला गया।

जिसमें वाराणसी की टीम ने देवीपाटन मंडल पर एक तरफा गोल करते हुए 6-0 से जीत दर्ज की। आठवां मुकाबला लखनऊ बनाम चित्रकूट मंडल के मध्य हुआ। इसमें लखनऊ की टीम ने चित्रकूट मंडल को 10- 2 से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। नौवा मुकाबला अयोध्या मंडल और मिर्जापुर मंडल के मध्य हुआ। जिसमें दोनों टीमें संघर्ष करती दिखी । दोनों टीमों का स्कोर 3-3 के बराबरी पर रहा।

यूएई कप्तान मुहम्मद वसीम ने तोड़ा रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड

एजेंसी

नई दिल्ली। शारजाह में खेले गए त्रिकोणीय श्रृंखला मुकाबले में यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वसीम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएई की पारी के तीसरे ओवर में वसीम ने अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब-उर-रहमान की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़कर यह उपलब्धि अपने नाम की। वसीम ने मैच में 37 गेंदों में 67 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। यूएई टीम 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। मुहम्मद वसीम के नाम बतौर कप्तान

अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 110 छक्के हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने बतौर कप्तान 35 मैचों में 105 छक्के लगाए थे। अब वसीम 110 छक्कों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

टी20आई में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के:

110 - मुहम्मद वसीम (यूएई)
105 - रोहित शर्मा (भारत)
86 - इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड)
82 - आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)
79 - कादोवाकी फ्लेमिंग (जापान)
69 - जोस बटलर (इंग्लैंड)

अरुणाचल टी20 चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ, पहले दिन केआरए डॉमिनेटर्स और कामेंग किंग्स ने दर्ज की जीत

एजेंसी

दरंग (असम)। अरुणाचल टी20 चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हो गई है। पहले दिन दो मैच खेले गए, जिसमें केआरए डॉमिनेटर्स और कामेंग किंग्स ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का पहला मैच केआरए डॉमिनेटर्स और सियांग स्टॉर्म के बीच खेला गया। मंगलदोई के दरंग स्थित मंगलदोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में खेले गए मैच में केआरए डॉमिनेटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। इसके जवाब में सियांग स्टॉर्म की टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। इस तरह मैच में केआरए डॉमिनेटर्स ने सियांग स्टॉर्म को 8 रनों से हरा दिया। दिन का दूसरा मैच कामेंग किंग्स और कुरुंग ब्लास्टर्स के बीच खेला गया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कामेंग किंग्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 190 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में कुरुंग ब्लास्टर्स की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर 156 रन ही बना सकी।

इस तरह यह मुकाबला कामेंग किंग्स ने 34 रन से जीत लिया। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल टी20 चैंपियनशिप 2025 में राज्य की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 16 सितंबर को खेला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अच्छे क्रिकेट मैदान न होने के कारण सरकार ने मंगलदोई स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया है।मंगलदोई खेल संघ के अध्यक्ष गुरुज्योति दास ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के इस कदम के प्रति आभार ज्ञापित किया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने सऊदी टूरिज्म कैंपेन का चेहरा

एजेंसी

रियाद। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी (एसटीए) के उपभोक्ता ब्रांड 'सऊदी, वेलकम टू अरेबिया' ने अपना नया वैश्विक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें दुनिया के फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो नज़र आ रहे हैं। इस कैंपेन का नाम 'आई कम फॉर फुटबॉल, आई स्टेड फॉर मोर' रखा गया है, जो यह संदेश देता है कि सऊदी अरब सिर्फ खेलों का नहीं बल्कि मनोरंजन, संस्कृति और फैशन का भी बड़ा केंद्र बन चुका है।

फिल्मी अंदाज़ में तैयार किए गए इस कैंपेन में रोनाल्डो को सऊदी अरब के अलग-अलग इवेंट्स का अनुभव करते दिखाया गया है। शुरुआत में वे स्टेडियम में बैठे अपने खेल से अन्य खेलों की तुलना करते दिखते हैं और फिर रंगीन दृश्यों के बीच दर्शकों के जुनून और जोश को महसूस करते हैं। यह दिखाता है कि सऊदी अब वैश्विक खेल और सांस्कृतिक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। यह कैंपेन सऊदी के सालभर चलने वाले

विविध खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोशनी डालता है, जो रियाद, जेद्दाह और अलउला में आयोजित होते हैं। इनमें फीफा वर्ल्ड कप 2034, एएफसी एशियन कप 2027, ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक्स 2027 और एशियन विंटर गेम्स 2029 जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। साथ ही फॉर्मूला-1, ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, गोल्फ, टेनिस और सऊदी प्रो लीग जैसे नियमित आयोजनों से यह देश खेलों का वैश्विक केंद्र बन रहा है। सऊदी न केवल खेलों में बल्कि कला, फैशन और मनोरंजन में भी तेजी से उभर रहा है। रियाद फैशन वीक, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आर्ट्स बिएनाले और सीजन फेस्टिवल्स इसके कैलेंडर का अहम हिस्सा हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कलाकार मंच साझा करते हैं। सऊदी के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा, सऊदी आज सांस्कृतिक असलियत, गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी और विश्वस्तरीय आयोजनों का अनोखा संगम बन चुका है। हम पर्यटकों को यादगार अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।÷ वहीं, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के सीईओ फहद हमीदअद्दीन ने बताया कि 2018 से अब तक सऊदी 100 से अधिक बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स की मेज़बानी कर चुका है और 2030 तक 150 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है।

न्यूज़ीलैंड टी20 सीरीज के लिए, मार्कस स्टॉइनिस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी

एजेंसी

मेलबर्न, 2 सितंबर (हि.स.)।ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें ऑलराउंडर मार्कस स्टॉइनिस की वापसी हुई है। उनके साथ मिच ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और जेवियर बार्टलेट की भी टीम में वापसी हुई है, जिससे अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्टॉइनिस की दावेदारी मज़बूत हो गई है।

36 वर्षीय स्टॉइनिस पिछले एक साल से न तो सेंट्रल और न ही स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार नवंबर 2024 में खेला था। इस साल फरवरी में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन टी20 लीग्स में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स और द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए अहम भूमिकाएं

निभाईं और दोनों टीमों को फाइनल तक पहुँचाने में योगदान दिया। हालांकि, विश्व कप टीम में जगह बनाना स्टॉइनिस के लिए आसान नहीं होगा। मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की भूमिका के लिए कैमरन ग्रीन, टिम डेविड और मिच ओवेन भी दावेदार हैं। ग्रीन न्यूज़ीलैंड सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि वे घरेलू एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड क्रिकेट पर ध्यान देंगे। वहीं ओवेन चोट (कन्कशन) से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं। मैथ्यू शॉर्ट भी चोट (साइड स्ट्रेन) से उबरकर टीम में वापसी कर रहे हैं। एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर चोटिल खिलाड़ियों की जगह मिली थी, लेकिन अब वे बाहर हो गए हैं। तेज़ गेंदबाज़ नाथन एलिस पितृत्व अवकाश के कारण इस दौरे से अनुपस्थित रहेंगे।

इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े खिलाड़ी भी नहीं खेलेंगे–मिचेल स्टार्क, जिन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और पैट कमिंस, जो पीठ की चोट से उबर रहे हैं और एशेज के लिए फिटनेस हासिल करने की कोशिश में हैं। तीन मैचों की टी20 सीरीज माउंट माउंगानुई में 1, 3 और 4 अक्टूबर को खेली जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम (टी20 बनाम न्यूज़ीलैंड):

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन द्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिच ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉइनिस, एडम ज़ैम्पा।

अफगानिस्तान की यूएई पर आसान जीत

शारजाह। अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 38 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज़ में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान ने बड़ा कीर्तिमान रचते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए। 26 वर्षीय राशिद ने 3 विकेट लेकर अपना आंकड़ा 165 पर पहुँचा दिया और न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ टिम साउदी (164 विकेट) को पीछे छोड़ दिया। राशिद ने ईथन डिसूज़ा (12), आसिफ खान (1) और ध्रुव पाराशर (1) को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाज़ी करते हुए 4 विकेट पर 188 रन बनाए। इब्राहिम जादरान (63 रन, 40 गेंद, 4 छक्के, 3 चौके) और सेदिकुल्लाह अतल (54 रन, 40 गेंद, 3 छक्के, 4 चौके) ने दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की। अतल का यह पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था। अंत में करीम जनत (23*, 10 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) और अजमतुल्लाह उमरजई (20*, 12 गेंद, 2 छक्के) ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर स्कोर को मज़बूती दी। यूएई के मुहम्मद रोहिद और सगीर खान ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई ने कप्तान मुहम्मद वसीम (67 रन, 37 गेंद, 6 छक्के, 4 चौके) की आतिशी पारी से धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने 23वां टी20ढ्ढ अर्धशतक जमाया, लेकिन उनके आउट होते ही टीम की लय बिगड़ गई और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद अफगानिस्तान ने सीरीज़ में वापसी की। पाकिस्तान पहले ही दोनों मैच जीत चुका है और अब मंगलवार को अफगानिस्तान से भिड़ेगा।

यूपी टी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स की धमाकेदार जीत, काशी रुद्राज को 59 रन से हराया

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश टी20 लीग (सीजन-3) के लीग मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काशी रुद्राज को 59 रन से मात दी। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 161 रन बनाए, जिसके जवाब में काशी रुद्राज की पूरी टीम 18.3 ओवर में 102 रन पर ढेर हो गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स की शुरुआत खराब रही और समर्थ सिंह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन विकेटकीपर आराध्य यादव ने 49 गेंदों में 79 रन की धमाकेदार

पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके अलावा समीर चौधरी ने 13 गेंदों पर 25 रन और करण शर्मा ने 30 रन बनाए। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 161 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी काशी रुद्राज की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही। कप्तान करण शर्मा ने जरूर 30 रन बनाए, जबकि सक्षम राय ने 24 रन जोड़े, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके। टीम 18.3 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। लखनऊ के लिए कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि शिवम मावी ने 4 विकेट लिए। इसके अलावा सुनील कुमार ने भी 2 विकेट हासिल किए।

इस जीत के साथ लखनऊ फाल्कन्स ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि काशी रुद्राज को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।

ओलंपिक चैंपियन इमान खलीफ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के जेंडर टेस्ट नियम के खिलाफ सीएएस में की अपील

एजेंसी

लुसाने। पेरिस ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अल्जीरियाई मुक्केबाज़ इमान खलीफ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के उस निर्णय के खिलाफ अपील की है, जिसमें उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया है जब तक कि वे अनिवार्य जेनेटिक सेक्स टेस्ट न कराएं। स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीएएस) ने बताया कि खलीफ ने यह अपील पिछले महीने दायर की थी। हालांकि, सीएएस ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के फैसले को तत्काल निलंबित करने की खलीफ की मांग को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि वह इस हफ्ते शुरू होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। खलीफ ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उस दौरान उन पर और चीनी ताइपे की लिन यू-टिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे। दोनों को 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से पूर्व शासी निकाय इंटरनेशनल

बॉक्सिंग एसोसिएशन (आईबीए) ने अज्ञात पात्रता परीक्षणों में विफल बताकर बाहर कर दिया था। हालांकि, आईबीए को लंबे समय से विवादों और कुप्रबंधन के कारण निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद आईओसी (अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति) ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग का संचालन किया और पुराने जेंडर पात्रता नियमों के आधार पर खलीफ व लिन दोनों को खेलने की अनुमति दी।नए शासी निकाय वर्ल्ड बॉक्सिंग को 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए मान्यता मिल चुकी है। इसी बीच, उसने इस साल मई में सभी खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य सेक्स टेस्टिंग की घोषणा की थी और इसमें विशेष रूप से खलीफ का नाम भी लिया था। हालांकि बाद में संगठन ने इस पर खेद जताया। खलीफ का लक्ष्य है कि वह लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में अपने वेल्टरवेट वर्ग का स्वर्ण पदक बचा सकें। वहीं, नई आईओसी अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री ने जेंडर पात्रता संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है।

लक्ष्य शूटिंग क्लब ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मनाया तीन दिवसीय शूटिंग महोत्सव

एजेंसी

मुंबई। ओलंपियन और कोच सुमा शिरुर के नेतृत्व में लक्ष्य शूटिंग क्लब (एलएससी) ने राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 29 से 31 अगस्त तक पनवेल और वाशी स्थित रेंजों पर तीन दिवसीय शूटिंग महोत्सव का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता सिर्फ एलएससी के खिलाड़ियों के लिए थी और इसका उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और युवा निशानेबाजों को प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान करना था। खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त इस अकादमी ने आयोजन को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न किया।प्रतियोगिता की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय खेल दिवस की शपथ से हुई। सुमा शिरुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रीय खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकल्प, अनुशासन और हर हार के बाद उठने की हिम्मत का प्रतीक है। मेरा सपना है कि एलएससी के माध्यम से हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने और भारतीय खेल भावना को मजबूत करने का अवसर मिले। पहले दिन पनवेल रेंज पर आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल क्वालिफिकेशन मुकाबले, जबकि वाशी रेंज पर एनआर राइफल, पिस्टल और ओपन साइट स्पर्धाएं आयोजित हुईं।

केकेएफआई उपाध्यक्ष प्रद्युम्न मिश्रा को मिला बीजू पटनायक खेल सम्मान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) के उपाध्यक्ष और ओडिशा खो-खो संघ के महासचिव प्रद्युम्न मिश्रा को खेलों के प्रोत्साहन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए बीजू पटनायक खेल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रीय खेल दिवस पर भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन में एक विशेष समारोह में ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरी बाबू कंभंपति ने प्रदान किया। बीजू पटनायक खेल सम्मान 2024 के अंतर्गत कई विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान देने वाले खिलाड़ियों और खेल हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रद्युम्न मिश्रा के साथ भारत के सबसे तेज धावक अनीमेश कुजुर को 100 मीटर और 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने और 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए सम्मानित किया गया। वेटलिफ्टिंग के दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार प्राप्ति विजेता बिजय कुमार सतपथी को उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रद्युम्न मिश्रा ने कहा, बीजू पटनायक खेल सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह पहचान सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी खिलाड़ियों, कोचों और प्रशासकों की है, जिन्होंने खो-खो को ओडिशा और पूरे भारत में ऊंचाई तक ले जाने के लिए अथक मेहनत की है। मैं यह पुरस्कार उन युवा खिलाड़ियों को समर्पित करता हूं, जिनका जुनून और मेहनत हमें निरंतर प्रेरित करता है। केकेएफआई और ओडिशा खेल परिवार के सहयोग से मैं खो-खो को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से प्रद्युम्न मिश्रा ओडिशा में खो-खो के विकास और प्रोत्साहन के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक रहे हैं। महासचिव के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया, जिनमें पुरी में आयोजित 57वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसने ओडिशा को पारंपरिक भारतीय खेलों के केंद्र के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर, कोचों के लिए उच्च स्तरीय कार्यशालाएँ और खे लो इंडिया प्रतिभा पहचान समिति (ईस्ट ज़ोन) में सेवा देकर जमीनी स्तर पर खो-खो को मजबूती प्रदान की। उनके नेतृत्व में पुरी में खो-खो अकादमी और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर की शुरुआत हुई, जबकि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एक समर्पित खो-खो स्टेडियम की स्थापना के लिए प्रयास जारी हैं। उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए, भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा, यह सम्मान न केवल ओडिशा के लिए बल्कि पूरे भारतीय खो-खो परिवार के लिए गर्व का क्षण है। प्रद्युम्न मिश्रा जी के अथक प्रयासों ने राज्य में खेल की एक मजबूत नींव रखी है और उनका नेतृत्व हमें राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रेरित करता है। बीजू पटनायक खेल सम्मान उनके कार्यों का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि खो-खो को राष्ट्रीय महत्व का खेल माना जाने लगा है। बीजू पटनायक खेल सम्मान ओडिशा का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों, कोचों, प्रशासकों और खेल योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। अन्य सम्मानित खिलाड़ियों में पैरा-एथलीट रखाल कुमार सेठी (श्रेष्ठ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन), शतरंज खिलाड़ी सत्यविक स्वाइन (उदीयमान जूनियर खिलाड़ी), खेल छात्रावास वॉलीबॉल कोच सुषमा नंदा (कोचिंग में उत्कृष्टता), बिमल कुमार राउल (खेल पत्रकारिता में उत्कृष्टता) और डॉ. सुदीप सतपथी (श्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी/सपोर्ट स्टाफ) बीजू पटनायक ब्रेवरी अवॉर्ड चित्तरंजन प्रधान और जीवन कुमार बेहेरा को प्रदान किया गया।

नौंदिता मेडिकेयर की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, मजबूत लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी ने शेयर 145 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 275.50 रुपये के स्तर पर हुई। मजबूत लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर की चाल में तेजी आ गई। लगातार हो रही लिवाली के सपोर्ट से कंपनी के शेयर 289.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए और इसी स्तर पर बंद हुए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 99.48 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। यानी आईपीओ निवेशकों का पैसा पहले दिन ही करीब दोगुना हो गया है। अनोंदिता मेडिकेयर का 69.50 करोड़ रुपये का आईपीओ 22 से 26 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

कमजोरी लिस्टिंग के बाद ग्लोबटियर इंफोटेक के शेयरों पर लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली।आईटी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी ग्लोबटियर इंफोटेक के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को काफी निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 72 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 57.60 रुपये के स्तर पर हुई। कमजोर लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर फिसल कर 54.72 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 17.28 रुपये यानी 24 प्रतिशत का नुकसान हो गया। ग्लोबटियर इंफोटेक का 31.05 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 28 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 2.04 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.63 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 27.44 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 5,00,800 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं।

आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज के बोझ को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 3.35 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 3.74 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 5.50 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 4 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 94.81 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अगस्त माह में यूपीआई से हुए 20 अरब ट्रांजिक्शन, 24.85 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑनलाइन भुगतान की लोकप्रियता के चलते एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अगस्त में 20 अरब मासिक लेन-देन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस दौरान मूल्य के लिहाज से 24.85 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जो पिछले साल इसी अवधि में 20.60 लाख करोड़ रुपये से 21 फीसदी अधिक है। ये आंकड़ा जुलाई में 25.08 लाख करोड़ रुपये था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि अगस्त में कुल लेन-देन की संख्या 20.01 अरब रही है, जो अगस्त 2024 में 14.9 अरब से 34 फीसदी की सालाना वृद्धि को दर्शाती है। एनपीसीआई के अनुसार मूल्य के लिहाज से अब तक का सबसे अधिक यूपीआई लेनदेन मई में 25.14 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। मात्रा के लिहाज से जुलाई में सबसे अधिक 19.47 अरब लेनदेन हुए थे। यूपीआई लेनदेन की राशि 21 फीसदी बढ़कर 24.85 लाख करोड़ रुपये रही। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 20.60 लाख करोड़ रुपये था। एनपीसीआई के जारी आंकड़ों के मुताबिक मात्रा के लिहाज से लेनदेन अगस्त, 2024 में 14.9 अरब से 34 फीसदी बढ़कर अगस्त, 2025 में 20.01 अरब हो गया। इस साल अगस्त के दौरान औसत दैनिक लेनदेन की संख्या 64.5 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि औसत दैनिक लेनदेन की राशि 80,177 करोड़ रुपये थी। ये उच्च-आवृत्ति खुदरा और बड़ी मात्रा में हस्तांतरण दोनों में यूपीआई की बढ़ती व्यापकता को दर्शाता है।

सेबी के नियमों का पालन न करने पर कोल इंडिया पर 10.72 लाख रुपये जुर्माना

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पर 10.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगाया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी को एनएसई और बीएसई से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर के नियम 17 के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि? उसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी के मानदंडों का पालन न करने पर उस पर 10.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीआईएल ने कहा कि यह गैर-अनुपालन उसकी किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं था और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी किए गए थे। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति सीआईएल के प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अगस्त में जीएसटी राजस्व संग्रह 6.5 फीसदी बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह अगस्त में सालाना आधार पर 6.5 फीसदी बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 1.75 लाख करोड़ रुपये था, जबकि पिछले महीने जून में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी महानिदेशालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि अगस्त में शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सलाना आधार पर 10.7 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में सकल घरेलू राजस्व 9.6 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात कर 1.2 फीसदी घटकर 49,354 करोड़ रुपये रह गया। जीएसटी रिफंड सलाना आधार पर 20 फीसदी घटकर 19,359 करोड़ रुपये रह गया। इससे पहले अप्रैल 2025 में जीएसटी राजस?व संग्रह बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। जीएसटी राजस्व संग्रह का ये आंकड़ा केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें दरों को युक्तिसंगत बनाने और कर स्लैब की संख्या कम करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जुलाई में देश में जीएसटी लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था।

टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाला

नई दिल्ली। भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) की 1991 बैच की अधिकारी टीसीए कल्याणी ने सोमवार को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाल लिया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली 29वीं अधिकारी हैं। उन्होंने रक्षा, दूरसंचार, उर्वरक, वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सूचना एवं प्रसारण, और गृह मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों में कार्य किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कल्याणी ने प्रौद्योगिकी को अपनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को निरंतर बढ़ावा दिया है। मुख्य लेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार ग्रहण करने से पहले कल्याणी गृह मंत्रालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए) के रूप में कार्यरत थीं, जहां उन्होंने भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक के बजट और लेखा-जोखा का निरीक्षण किया।

एनआईएस मैनेजमेंट की स्टॉक मार्केट में फीकी एंट्री, कमजोर लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी एनआईएस मैनेजमेंट के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में सुस्त शुरुआत करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 111 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 2.70 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 108 रुपये के स्तर पर हुई। कमजोर लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर फिसल कर 102.60 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 8.40 रुपये यानी 7.48 प्रतिशत का नुकसान हो गया। एनआईएस मैनेजमेंट का 60.01 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 28 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 3.13 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 2.12 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 9.15 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.10 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 51.75 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 7.44 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 16.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 18.38 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 18.67 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 8 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 405.33 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में कंपनी पर कर्ज में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 87.22 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 91.11 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी के कर्ज में मामूली कमी आई और ये घट कर 83.78 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे सोना और चांदी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने आज सर्राफा बाजार में तेजी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,0,090 रुपये से लेकर 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 97,250 रुपये से लेकर 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह ही चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,06,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 97,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 97,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,06,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 97,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे साल की 5 लाख करोड़ से अधिक की खरीदारी

नई दिल्ली। साल 2025 के पहले आठ महीने के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी करके घरेलू शेयर बाजार को काफी सहारा दिया है। इसके पहले 2024 में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 5.25 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। अभी 2025 के चार महीने बाकी हैं। ऐसे में घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी का आंकड़ा इस साल के अंत तक काफी ऊपर जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार लंबे समय से दबाव में कारोबार कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रही उठापटक और भारत पर अमेरिकी टैरिफ लादे जाने की वजह से घरेलू शेयर बाजार का सेंटिमेंट लगातार बिगड़ा है। इस वजह से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करके अपने पैसे की निकासी करने में लगे हुए हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों

(डीआईआई) ने जमकर खरीदारी करके शेयर बाजार को अपनी ओर से पूरा सहारा देने का काम किया है। एनएसई के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक, बीमा कंपनियों और अन्य घरेलू संस्थानों ने 2025 में अगस्त के महीने तक कुल 5.13 लाख करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये का था। 2023 में ये आंकड़ा 1.81 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह 2022 में घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 2.76 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी। आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार में घरेलू खरीद में आया ये उछाल विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के बीच आया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2024 में शेयर बाजार में बिकवाली करके लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का ये ट्रेंड 2025 में भी जारी है। इस साल विदेशी निवेशक घरेलू शेयर बाजार से 1.30 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। धामी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत धामी के अनुसार 2025 में जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली करके अपने पैसे की निकासी कर रहे हैं, तब घरेलू शेयर बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भरपूर सहारा दिया है। लगातार दूसरे साल पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी करके घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शेयर बाजार अब विदेशी निवेशकों की दया ।

रिकॉर्ड लो लेवल तक गिरने के बाद संभला रुपया, डॉलर की तुलना में 1 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

एजेंसी

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में तेजी आने के कारण मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने के बावजूद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की खरीदारी के कारण आखिरकार 1 पैसे की सांकेतिक तेजी के साथ बंद होने में सफल रहा। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 1 पैसे उछल कर 88.20 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 88.21 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.23 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद रुपया 11 पैसे फिसल कर अभी तक सबसे निचले स्तर 88.32 तक गिर गया। हालांकि इसके बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की खरीदारी के कारण मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक बढ़ने लगी, जिससे रुपये की स्थिति में भी सुधार होने लगा। डॉलर की आवक बढ़ने के कारण भारतीय मुद्रा 9 पैसे की मजबूती के साथ 88.12 के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि बाद में एक बार फिर डॉलर की मांग तेज हो जाने के कारण रुपये पर दबाव बनने लगा। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 1 पैसे की सांकेतिक उछाल के साथ 88.20 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया।

देश का चालू खाता घाटा अप्रैल-जून तिमाही में घटकर जीडीपी का 0.2 फीसदी : आरबीआई

एजेंसी

नई दिल्ली/मुंबई। देश का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में घटकर 2.4 अरब डॉलर रह गया जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.2 फीसदी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि चालू खाता संतुलन में ये सुधार मुख्य रूप से सेवाओं के निर्यात का नतीजा है। आरबीआई के मुताबिक भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में तेजी से घटकर 2.4 अरब डॉलर यान जीडीपी का 0.2 फीसदी रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8.6 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.9 फीसदी) था। आरबीआई के

मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में चालू खाता 13.5 अरब डॉलर के अधिशेष में था, जो जीडीपी का 1.3 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में देश का चालू खाता घाटा 23.3 अरब डॉलर रहा, जो जीडीपी का 0.6 फीसदी है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 26 अरब डॉलर (0.7 फीसदी) रहा था। रिजर्व बैंक के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 68.5 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित?त वर्ष की इसी अवधि में 63.8 अरब डॉलर था। सेवाओं से शुद्ध प्राप्तियां बढ़कर 47.9 अरब डॉलर हो गईं, जो एक साल पहले इसी अवधि में 39.7 अरब डॉलर थीं। आरबीआई के मुताबिक जून तिमाही में व्यवसायिक सेवाओं और कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात में सालाना आधार पर अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय खाते के संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पहली तिमाही में 5.7 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ, जबकि पिछले वित?त वर्ष की इसी अवधि में यह 6.2 अरब डॉलर था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के रूप में 1.6 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया जो पिछले वित्त वर्ष 0.9 अरब डॉलर था।

दक्षिणी राज्यों की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया

एजेंसी

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने दक्षिण राज्यों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कर्नाटक, केरल और तेलंगाना राज्यों में मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना के समर्थकों ने भाग लिया। मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाकर समस्याओं के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में कर्नाटक में 3,658 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित 5 मुद्दों की समीक्षा की गई। केरल में 5,002 करोड़ रुपये की लागत वाली 2 परियोजनाओं से संबंधित 2 मुद्दों की पड़ताल की गई, जबकि तेलंगाना में 1,934 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 3 परियोजनाओं से संबंधित 6 मुद्दों पर चर्चा की गई। डीपीआईआईटी सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।

एटीएफ की कीमत में 1.4 फीसदी की कटौती, नई दरें लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में 1.4 फीसदी तक की कटौती की है। एटीएफ के दाम में यह कटौती एक जुलाई से कीमतों में लगातार दो मासिक वृद्धि के बाद वैश्विक मानक दरों में कमी के चलते की गई है। नई दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत 1,308.41 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 1.4 फीसदी घटकर 90,713.52 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में एटीएफ की कीमत 86,077.14 रुपये घटकर 84,832.83 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई, जबकि चेन्नई और कोलकाता में कीमतें क्रमशः 94,151.96 रुपये और 93,886.18 रुपये प्रति किलोलीटर हो गईं। उललेखनीय है कि वैट जैसे स्थानीय करों के आधार पर शहरों में कीमतें अलग-अलग होती हैं। विमान ईंधन के मूल्य कटौती से वाणिज्यिक एयरलाइनों पर बोझ कम होगा, जिनके लिए ईंधन परिचालन लागत का करीब 40 फीसदी हिस्सा है। हालांकि, इस संबंध में एयरलाइनों से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी है।

लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, मजबूती के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी

नई दिल्ली। अगस्त के आखिरी तीन कारोबारी दिनों में गिरावट का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार ने आज सितंबर महीने की शुरुआत जोरदार मजबूती के साथ की। माना जा रहा है कि जीडीपी के मजबूत आंकड़े, चीन के तियानजिन में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन से आ रही सकारात्मक खबर, आईटी शेयरों में आई तेजी और शेयर बाजार में निचले स्तर से हुई खरीदारी के सपोर्ट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक आज बढ़त बनाने में सफल रहे। आज के कारोबार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद दिन के पहले सत्र के कारोबार में लिवालों और बिकवालों के बीच जोर आजमाइश होती रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में भी उतार-चढ़ाव होता रहा। दोपहर 12 बजे के बाद खरीदार पूरी तरह से बाजार पर हावी हो गए, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल लगातार तेज होती गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.70 प्रतिशत और निफ्टी 0.81 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

आज दिन भर के कारोबार के दौरान आईटी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी और मेटल सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसके अलावा बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे निफ्टी का ऑटोमोबाइल इंडेक्स आज 2.80 प्रतिशत तक उछल गया। इसी तरह आईटी इंडेक्स भी 1.59 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद होने में सफल रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.64 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 1.49 प्रतिशत की मजबूती के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 448.90 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 443.65 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 5.25 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,380 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,800 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,387 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 193 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,805 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,944 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 861 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 23 शेयर बढ़त के साथ और 7 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 42 शेयर हरे निशान में और 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 19.34 अंक के मामूली बढ़त के साथ 79,828.99 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल ऊपर नीचे होने लगी। दोपहर 12 बजे तक उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद सेंसेक्स को खरीदारों का सपोर्ट मिल गया, जिसके कारण इस सूचकांक ने रफ्तार पकड़ ली। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 597.19 अंक उछल कर 80,406.84 अंक के स्तर तक पहुंच गया।

रूस पर यूरोपीय संघ नेता के विमान की नेविगेशन प्रणाली में हस्तक्षेप का संदेह

एजेंसी

सोफिया (बुल्गारिया)। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के विमान को बुल्गारिया के ऊपर उड़ान के दौरान जीपीएस सिग्नल जैमिंग का सामना करना पड़ा, जिसे अधिकारियों ने रूस की ओर से किए गए संभावित हस्तक्षेप के रूप में देखा है। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता एरियाना पोदेस्ता ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से प्लोवदीव हवाई अड्डे पर उतरा और वॉन डेर लेयेन अपनी पूर्वी यूरोपीय संघ सदस्य देशों की निर्धारित यात्रा जारी रखेंगी। प्रवक्ता ने कहा, हमें बुल्गारियाई अधिकारियों से जानकारी मिली है कि यह हस्तक्षेप रूस की जानबूझकर की गई कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। हम पुष्टि कर सकते हैं कि जीपीएस जैमिंग हुई थी। यह घटना उन कई मामलों में से एक है, जिनमें रूस पर जीपीएस सैटेलाइट नेविगेशन में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं। पिछले कुछ महीनों से रूस की सीमा से सटे देश फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया बार-बार ऐसे हस्तक्षेप की चेतावनी देते रहे हैं, जिससे उड़ानों, जहाजों और ड्रोन पर असर पड़ रहा है। बुल्गारियाई प्रशासन ने बताया कि वारसॉ से प्लोवदीव की उड़ान के दौरान विमान का जीपीएस सिग्नल बाधित हो गया। लैंडिंग के समय सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया, जिसके बाद पायलटों को वैकल्पिक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

चीन और रूस ने दिया ईरान का साथ, यूरोपीय देशों के प्रतिबंध बहाली की पहल का विरोध

दुबई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन और रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए यूरोपीय देशों द्वारा तेहरान पर पुराने प्रतिबंध फिर से लागू करने के कदम को खारिज कर दिया। यह प्रतिबंध करीब एक दशक पहले परमाणु समझौते के तहत हटाए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा लागू किए गए तथाकथित स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत प्रतिबंध बहाली की पहल को लेकर चीन, रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें इस कदम को कानूनी और प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण बताया गया। गौरतलब है कि चीन और रूस भी 2015 के ईरान परमाणु समझौते के हस्ताक्षरकर्ता रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। हालांकि, अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। यूरोपीय देशों ने पिछले हफ्ते यह तंत्र सक्रिय किया था, यह आरोप लगाते हुए कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते के तहत ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से राहत मिली थी, बदले में उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखना था।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों का दुरुपयोग है।

चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को प्रधानमंत्री ओली के सलाहकार ने किया खारिज

काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आर्थिक सलाहकार डॉ. युवराज खतिवडा ने चीनी विदेश मंत्रालय के उस बयान को झूठ बताया है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव (जीएसआई) के लिए समर्थन व्यक्त किया है। डॉ. खतिवडा ने कहा कि इस बैठक के दौरान उन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चर्चा हुई, जिन्हें दोनों पक्ष समझौतों और सहमतियों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता देंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ओली और चीनी राष्ट्रपति शी ने 31 अगस्त को तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेपाल ने चीन के प्रस्तावित वैश्विक विकास पहल (जीडीआई), वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसआई) और वैश्विक सभ्यता पहल (जीसीआई) का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ओली तथा चीनी राष्ट्रपति शी के बीच बैठक में शामिल डॉ. खतिवडा ने कहा कि नेपाल सरकार, नेपाल के संविधान और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगी। खतिवडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली की यात्रा मुख्यतः एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए है। शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत में किसी समझौते या सहमति पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

प्रधानमंत्री ओली ने चीन में कंबोडिया, मालदीव और लाओ के राष्ट्रध्यक्षों से की द्विपक्षीय मुलाकात

काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। उन्होंने कंबोडिया के अपने समकक्ष हुन मानेत, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और लाओ के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल-कंबोडिया संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने संबंधों को और मजबूत करने के लिए उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के महत्व को भी रेखांकित किया। बैठक में ओली के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व उप प्रधानमंत्री और सांसद पूर्ण बहादुर खडका, शिक्षा मंत्री रघुजी पंत, पर्यटन मंत्री बद्री पांडे, पूर्व मंत्री और आर्थिक सलाहकार डॉ. युवराज खतिवडा, सांसद छवि लाल बिश्वकर्मा और विदेश सचिव अमृत बहादुर राई शामिल थे।

भारत के साथ दशकों की साझेदारी को ट्रंप ने 'तहस-नहस' किया : पूर्व अमेरिकी एनएसए बोल्टन

एजेंसी

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ दशकों से चली आ रही साझेदारी को तहस-नहस कर दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में भारत के साथ दशकों की साझेदारी को बिगाड़ दिया है। ट्रंप ने भारत को रूस और चीन के करीब जाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने बताया कि ट्रंप 2.0 से पहले, अमेरिका ने भारत को शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और चीन के साथ उसके लगाव से दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका,

दशकों से भारत को सोवियत संघ और रूस से पुराने रिश्तों, खासकर हथियारों की खरीद, से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत को चीन के खतरे के बारे में चेतावनी दी, जिसका प्रतीक एशियाई सुरक्षा चतुर्भुज (जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) है बोल्टन ने यह भी बताया कि ट्रंप प्रशासन ने कई कदम उठाए, जैसे व्यापार वार्ताओं को अचानक रोकना, जिससे भारत नाराज हुआ। जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत सोच रहा था कि वह ट्रंप के साथ व्यापार समझौते के करीब है, जैसा कि ब्रिटेन ने किया, लेकिन ट्रंप ने इसे नजरअंदाज कर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ थोप दिया। उन्होंने रूस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। ट्रंप ने चीन, जो रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है, पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। बोल्टन ने दावा किया कि ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, जिससे स्थिति और खराब हो गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तो स्थिति पहले बिगड़ी, लेकिन बाद में शांत हो गई। ट्रंप ने इसका पूरा श्रेय खुद लिया और कहा कि उन्होंने इस साल छह या सात युद्ध रोके, जिसके लिए वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। इससे भारत बहुत नाराज है।

रूस के राष्ट्रपति से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने की मुलाकात

एजेंसी

काठमांडू। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियांजिन में मौजूद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। यह बैठक हुई और तियांजिन के मेक्सियांग सम्मेलन केंद्र में लगभग आधे घंटे तक चली। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी उड़ान का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ओली के साथ दौरे पर गए उनके आर्थिक सलाहकार डॉ युवराज खतिवडा के अनुसार, प्रधानमंत्री ओली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने का भी प्रस्ताव रखा है।खतिवडा ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने रूस में नेपाली छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने पर भी चर्चा की है। उन्होंने लगभग 25 मिनट तक वन टू वन बैठक भी की तथा सरकारी टीम के साथ लगभग 15 मिनट तक चर्चा की। आज ही प्रधानमंत्री ओली ने अपने चीन भ्रमण के दौरान कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु से भी मुलाकात की है। को, उन्होंने टियांजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ बधाई दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने चीन में चावल के मुख्य रोपण क्षेत्र का दौरा किया था।

सूडान में भीषण भूस्खलन, 1000 से अधिक लोगों की मौत

एजेंसी

ख़ारतूम/दारफ़ुर। पश्चिमी सूडान में लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद मर्रा पर्वत क्षेत्र में आए भीषण भूस्खलन से कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (स्रस्र) ने इस आपदा की पुष्टि करते हुए बताया कि तारासिन गांव का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया और केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया।

मानवीय आपदा और सहायता की अपील

संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तत्काल मानवीय सहायता भेजने की अपील की है। भूस्खलन से प्रभावित इलाका दुर्गम और सुदूर है, जिससे राहत कार्य बेहद मुश्किल हो रहा है।

संघर्षग्रस्त क्षेत्र में नई त्रासदी

यह इलाका वर्तमान में सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी के नियंत्रण में है, जो सूडानी सेना के साथ मिलकर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ (ऋस्र) के खिलाफ लड़ रही है। गृहयुद्ध के चलते पहले से ही

हजारों लोग विस्थापित होकर मर्रा पर्वत की शरण ले चुके थे। अब इस प्राकृतिक आपदा ने हालात और बदतर बना दिए हैं।

युद्ध और भुखमरी की मार

अप्रैल 2023 में सेना और ऋस्र के बीच छिड़े संघर्ष ने देश को भुखमरी और जनसंहार की स्थिति में धकेल दिया है। अमेरिका के एक अधिकारी के अनुसार, 2023 से अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1.2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। दारफ़ुर क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर आए वक्तव्य पर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री ओली से जवाब मांगा

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान पर नेपाल में राजनीतिक भूचाल आ गया। अब इस बयान को लेकर संसद की अंतराष्ट्रीय संबंध समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जवाब मांगा है। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से मुलाकात के बाद वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर नेपाल की ओर से ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव (जीएसआई) का समर्थन करने की बात उल्लेख की गई है। इसको लेकर नेपाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सभी दलों ने इसका विरोध किया है। संसद की अंतराष्ट्रीय संबंध समिति के सभापति राजकिशोर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली के चीन भ्रमण से लौटते ही इस विषय पर जवाब तलब किया गया है। प्रधानमंत्री को संसदीय समिति में उपस्थित होकर इस विषय पर नेपाल सरकार की औपचारिक धारणा रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीएसआई चीन द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य गठबंधन है। चीन की तरफ से जारी बयान में नेपाल के समर्थन

की बात देश की विदेश नीति के खिलाफ है। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि नेपाल की संसद में सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया है कि हम किसी भी देश की सुरक्षा या सैन्य रणनीति का अंग नहीं बन सकते हैं। संसदीय समिति की बैठक के बाद अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने कहा है कि चीन के बयान के बाद नेपाल सरकार खासकर प्रधानमंत्री से उनकी इस विषय पर स्पष्ट धारणा रखने के लिए उन्हें संसदीय समिति में स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ इस समय चीन के भ्रमण पर रहे उनके आर्थिक सलाहकार डा युवराज खतिवड़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान जीएसआई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। खतिवड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि चीन का बयान गलत और भ्रामक है। प्रधानमंत्री के भ्रमण दल में सहभागी शिक्षा मंत्री रघुजी पंत ने भी कहा कि चीन का बयान एकतरफा है और इससे नेपाल का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चीन की तरफ से आए बयान में कोई सच्चाई नहीं है।

कीव ने एससीओ समिट के बयान में रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र न होने पर जताई नाराजगी

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज, 20 पेज के तियानजिन घोषणा पत्र में रूस के यूक्रेन पर युद्ध का जिक्र न होना बहुत ही आश्चर्यजनक और नकारात्मक संकेत है। यूक्रेन ने कहा कि यह यूरोप में हुई सबसे बड़ी आक्रामकता है, जो विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे गंभीर मानी जाती है, और इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज में इसका उल्लेख न होना काफी हैरान करने वाला है। जबकि घोषणा पत्र में कई अन्य युद्धों, आतंकवादी हमलों और विश्व के घटनाक्रम का जिक्र है, रूस-यूक्रेन युद्ध की चुप्पी साफ तौर पर एक बड़ी चूक है। यूक्रेन का कहना है कि बिना रूस की आक्रामकता का न्यायसंगत अंत किए, हम वैश्विक विकास, अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा, संयुक्त

राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों के स्थिर विकास की बात नहीं कर सकते।

यूक्रेन ने इस बात पर जोर दिया है कि एससीओ समिट के बयान में रूस-यूक्रेन युद्ध का उल्लेख न होना, मास्को के कूटनीतिक प्रयासों की असफलता का परिचायक है। रूस कोशिश कर रहा था कि विश्व को इस युद्ध को लेकर दो हिस्सों में बांट दे और यह धारणा बनाई जाए कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर के देशों में रूस की आक्रामकता को लेकर सकारात्मक सोच है। लेकिन इस बार रूस की यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन का मानना है कि मास्को अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एससीओ के सदस्य देशों की राय को एक ऐसी स्थिति में लाने में असफल रहा जो उसके पक्ष में हो। यूक्रेन ने पुनः सभी शांति शांतिप्रिय देशों से अपील की है कि वे रूस की आक्रामकता का आकलन करते समय अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करें। यूक्रेन ने चीन की महत्वपूर्ण भूराजनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीजिंग से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। यह शांति तभी संभव होगी जब सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान करें।

सैन्य परेड में शामिल होने बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुंचे प्रधानमंत्री ओली

एजेंसी

काठमांडू,। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली टियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलन के बाद बीजिंग पहुंचे हैं। सैन्य परेड में शामिल होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने बुलेट ट्रेन का सफर किया है। प्रधानमंत्री ओली ने अपने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर बुलेट ट्रेन के जरिए टियांजिन से बीजिंग की यात्रा करने की जानकारी दी है। बीजिंग पहुंचने पर चीनी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात चीनी

उपराष्ट्रपति हान झेंग से होनी है। उपराष्ट्रपति की ओर से आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भी नेपाली प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा।इससे पहले टियांजिन में प्रधानमंत्री ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। अपनी यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में नेपाली प्रतिनिधिमंडल 3 सितंबर को बीजिंग में फासीवाद और जापानी आक्रामकता के खिलाफ युद्ध में चीन की जीत के 80वीं वर्षगांठ समारोह में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल होगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल उसी दिन नेपाल लौटेगा।

उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन विशेष बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर बीजिंग रवाना

एजेंसी

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी विशेष बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर प्योंगयांग से चीन के लिए मंगलवार को रवाना हो गए। वे बीजिंग में बुधवार को होने वाली 'विक्ट्री डे' परेड में हिस्सा लेंगे। चीन के इस परेड में किम जोंग उन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। उत्तर कोरिया स्टेट मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोरियाई वर्कर्स पार्टी के महासचिव और कोरियाई लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के राज्य मामलों के अध्यक्ष किम जोंग उन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए 1 सितंबर को अपनी ट्रेन से

प्योंगयांग से रवाना हुए। उनकी ट्रेन 2 सितंबर की सुबह सीमा पार कर गई। किम जोंग के साथ कोरियाई पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय समिति और डीपीआरके सरकार के प्रमुख अधिकारी यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा में 24 घंटे तक का समय लग सकता है और वे मंगलवार को बीजिंग पहुंचेंगे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने बीजिंग की यात्रा के लिए एक घंटे की उड़ान के विकल्प को छोड़कर प्योंगयांग से बीजिंग तक ट्रेन में लगभग 24 घंटे के सफर को चुना। किम जोंग उन की इस विशेष ट्रेन का आधिकारिक नाम- तायांग-हो- है। जिसमें अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ शाही सुविधाएं हैं।

खास है किम जोंग उन की बख्तरबंद ट्रेन

दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि किम की निजी ट्रेन बुलेटप्रूफ खिड़कियों, अभेद्य आवरण, रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए विशेष जालीदार आवरण और मोटार से लैस है। कवच और उपकरणों से लदी, तायांग-हो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती है। शाही सुविधाएं और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है। इसकी रफ्तार 50-60 किमी/घंटा तक है।

वेनेजुएला के मादुरो ने कहा- उनका देश शांतिपूर्ण, लेकिन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा

एजेंसी

कैरेकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि उनका देश पिछले 100 वर्षों में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर कैरेबियाई सागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाकर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। काराकास में सैन्य अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदुरो ने कहा, 'वेनेजुएला 100 वर्षों में हमारे महाद्वीप पर देखे गए सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई।' उन्होंने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला एक शांतिप्रिय देश है लेकिन वह धमकियों के आगे नहीं झुकेगा।

हाल के हफ्तों में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के नजदीकी कैरेबियाई जलक्षेत्र में बड़ी तैनाती की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान का हिस्सा है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है, जिसे माइग्रेशन रोकने और दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करने की रणनीति से जोड़ा गया है। वहीं, वेनेजुएला ने बार-बार अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है कि उसका

शासन अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में शामिल है। अगस्त की शुरुआत में अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर मिलने वाले इनाम को दोगुना कर 50 मिलियन डॉलर कर दिया था। मादुरो और आंतरिक मंत्री दियोसदादो काबेलो ने अमेरिकी नौसैनिक तैनाती को हस्तक्षेप का बहाना बताते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जर्मनी के उद्यमियों से किया निवेश का आग्रह

एजेंसी

बर्लिन। तमिलनाडु में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री एम. के स्टालिन इन दिनों जर्मनी और ब्रिटेन की एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे फिलहाल जर्मनी में और फिर इंग्लैंड में बसे तमिलों और वहां के निवेशकों और उद्यमियों से तमिलनाडु आने और निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन सबसे पहले चेन्नई से जर्मनी के लिए रवाना हुए। उनके डसेलडोर्फ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वहां रहने वाले तमिलों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनका स्वागत फूलों और गुब्बारों से किया गया, जिन पर पिता लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यूरोपीय तमिलों द्वारा आयोजित भव्य तमिल ड्रीम कार्यक्रम में शामिल हुए। जर्मनी में रहने वाले तमिल प्रवासियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, जर्मनी में रहने वाले तमिल रिश्तेदारों, जिन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया है, उनकी ऊंचाइयों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनके स्वागत के उत्साह से मैं अभिभूत हो गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि विदेशों में रहने वाले तमिल अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और अपनी संस्कृति व भाषा का संरक्षण व सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने द्रविड़ मॉडल सरकार के तहत तमिलनाडु में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश और बाढ़ से 24 लाख लोग प्रभावित, हालात बिगड़ने की आशंका

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ मानसूनी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और एक हजार से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के हवाले से कहा कि यह क्षेत्रीय इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक है। पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने कहा कि भारी बारिश और उफनती नदियों के कारण पूरे प्रांत में 3,100 से ज्यादा गांव और लगभग 2,900 बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। लगातार मानसूनी बारिश और बाढ़ के पानी ने पूरे पाकिस्तान में खेतों को बर्बाद कर दिया है। कटाई के लिए तैयार फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे देश में खाद्य संकट और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे बड़े प्रांत में पिछले सप्ताह आई विनाशकारी बाढ़ से सैकड़ों गांव, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी भर गया है। मवेशी बह गए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं।

बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पाकिस्तान में यूएन रेजिडेंट और मानवीय समन्वयक मोहम्मद याह्या ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह सामान्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अब पूरे पाकिस्तान के लिए भय और तबाही लेकर आ रहा है।

पंजाब के हाफिजाबाद में जलमग्न खेतों का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जहां तक नजर जाती है, वहां तक धान के खेत बाढ़ की चपेट में हैं। किसानों को अब अगले बुआई सीजन तक बिना फसल या आय के रहना होगा। याह्या ने कहा, 'यह तो बस शुरुआत है। आने वाले हफ्तों में और तेज बारिश हो सकती है। जैसे-जैसे पानी दक्षिण की ओर बढ़ेगा, इससे परिवारों के विस्थापन और विनाश का खतरा और ज्यादा पैदा होगा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से चिनाब नदी का पानी मंगलवार को पंजाब के मुल्तान जिले तक पहुंच सकता है और रावी नदी के जल में मिल सकता है।

पीडीएमए के अनुसार, पंजाब में पंजनद नदी का जलस्तर 5 सितंबर को अपने चरम पर पहुंचने की आशंका है, जबकि सतलुज नदी का पानी सुलेमानकी और हेड इस्लाम सहित बैराजों की ओर बढ़ रहा है। पूरे पंजाब प्रांत में दो और दिनों तक मानसूनी बारिश का अनुमान है, जिससे राहत अभियान बाधित हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत के मैदानी इलाकों में 100 से 200 मिमी के बीच भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ में कम से कम 164 लोगों की जान चली गई, जबकि 582 अन्य घायल हो गए।

स्थानीय समाचार

शैलेंद्र कुमार ने एमआरसीएफसी खुडवानी का दौरा किया, समशीतोष्ण धान जैव विविधता की लाइव प्रदर्शनी में हुए शामिल

कुलगाम 02 सितंबर। कृषि उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार ने शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर के अंतर्गत फील्ड क्रॉप्स के लिए पर्वतीय अनुसंधान केंद्र खुडवानी का दौरा किया और समशीतोष्ण धान जैव विविधता की लाइव प्रदर्शनी में भाग लिया।

दौरे के दौरान प्रमुख सचिव ने अनुसंधान परीक्षण स्थलों का विस्तृत भ्रमण किया और उन्हें केंद्र में चल रहे अनुसंधान एवं बीज उत्पादन कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

उन्हें यह भी बताया गया कि यह केंद्र पिछले आठ दशकों से धान एवं अन्य फील्ड क्रॉप्स के अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान देता आ रहा है और विशेष रूप से जर्मप्लाज्म संरक्षण कार्यक्रम पर केंद्रित रहा है।

प्रमुख सचिव के साथ इस अवसर पर स्कॉस्ट-कश्मीर के उपकुलपति प्रो. नज़ीर अहमद गनी, उपायुक्त कुलगाम अथर आमिर, निदेशक कृषि कश्मीर, निदेशक अनुसंधान, निदेशक योजना, एडीसी कुलगाम, कृषि विभाग के अधिकारी, एमआरसीएफसी खुडवानी के वैज्ञानिक, दक्षिण कश्मीर केवीके के कार्यक्रम समन्वयक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान शैलेंद्र कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मांग-आधारित और विकासोन्मुखी अनुसंधान किया जाए ताकि जम्मू-कश्मीर में अनाज की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटा जा सके। उन्होंने विशेष रूप से तेल बीज उत्पादन क्षमता बढ़ाने और इसे 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार तक पहुँचाने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने किसानों तक उन्नत व सिद्ध तकनीकों को फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही केंद्र की अनुसंधान, विकास और शैक्षिक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर स्कॉस्ट-कश्मीर के उपकुलपति प्रो. नज़ीर अहमद गनी ने खुडवानी केंद्र को एक आदर्श संस्थान के रूप में बधाई दी और इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्राप्त प्रतिष्ठा के लिए सराहा।

धान की प्रमुख समस्या ब्लास्ट रोग का उल्लेख करते हुए प्रो. गनी ने कहा कि एमआरसीएफसी खुडवानी भारत में राइस ब्लास्ट स्क्रीनिंग का नोडल केंद्र है, जिससे इसका राष्ट्रीय स्तर पर फसल सुरक्षा अनुसंधान में विशेष महत्व है।

एमआरसीएफसी खुडवानी के प्रमुख डॉ. नजीब-उल-रहमान सोफी ने केंद्र की एक व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1942 में स्थापना से लेकर अब तक की उल्लेखनीय उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया। उन्होंने बताया कि यह केंद्र धान, सरसों और गेहूँ की नई प्रजातियाँ विकसित करने में अग्रणी रहा है, जिससे उत्पादन, गुणवत्ता और क्षेत्र कवरेज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डॉ. नजीब ने यह भी अवगत कराया कि किस प्रकार यह संस्थान 80 वर्षों से अधिक की निरंतर वैज्ञानिक सेवा के परिणामस्वरूप आज एक प्रीमियर षि अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

पूर्व विधान पार्षद ने उपराज्यपाल से भेंट की

श्रीनगर 02 सितंबर। पूर्व विधान पार्षद ज़फ़र इक़बाल ख़ान मन्हास ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की।

उन्होंने घाटी से फलों के सुचारू परिवहन के लिए मुगल रोड पर 10 टायर वाले ट्रकों की आवाजाही और निकी चंचमराग-शादाब शोपियां से दुबजेन सड़क पर काम शुरू करने से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए।

फिल्म अभिनेत्री प्रीति सप्रू ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की

श्रीनगर 02 सितंबर। फिल्म अभिनेत्री सुश्री प्रीति सप्रू ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की। उनके साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मुख्य सलाहकार परमजीत सिंह चंडोक, फिल्म अभिनेता तेज सप्रू और संजीव सराफभी थे। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में एक`श मंत्रालय के अनुसार, डॉ. दीपक मित्तल (आईएफएस 1998) को संयुक्त अरब अमीरात में भारस्मारक कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी पहल के बारे में जानकारी दी।

योगी सरकार का उच्च शिक्षा में बड़ा कदम - तीन विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी

लखनऊ, 02 सितंबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के तीन नवगठित विश्वविद्यालयों—गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद), मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर) और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर) में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसमें 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह निर्णय विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने के साथ-साथ प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार स्पष्ट किया है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा और रोजगार दोनों उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में नए पदों का सृजन इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जो उच्च शिक्षा को सशक्त और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

468 अस्थायी शिक्षणेतर पद

प्रत्येक विश्वविद्यालय में 156 अस्थायी शिक्षणेतर पद सृजित किए गए हैं, जो 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे और आवश्यकतानुसार समाप्त भी किए जा सकते हैं।

इन पदों में फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, अवर अभियंता, आशुलिपिक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, वैयक्तिक सहायक, लेखाकार, प्रधान सहायक, चिकित्साधिकारी और स्टाफ नर्स जैसे पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से की जाएगी।

480 आउटसोर्सिंग पद

इसके अलावा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 160 पद वाह्य सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से पूरे किए जाएंगे, जिससे कुल 480 पद बनते हैं। इनमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छकार, चौकीदार, माली, चपरासी, वाहन चालक और पुस्तकालय परिचर जैसे पद शामिल हैं। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नियुक्तियों में आरक्षण से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा।

राज्य कर विभाग ने करदाताओं की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए

जम्मू, 2 सितंबर। जम्मू और कश्मीर, राज्य कर विभाग (एसटीडी) ने ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित समस्याओं में करदाताओं की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। ई-वे बिल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, करदाता ई-वे बिल जनरेशन में त्रुटियों, सिस्टम की गड़बड़ियों या अनुपालन आवश्यकताओं पर स्पष्टीकरण जैसी समस्याओं के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर समर्पित सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये समर्पित हेल्पलाइन आधिकारिक कार्य समय के दौरान संचालित होंगी और इनमें जीएसटी और ई-वे बिल नियमों से अच्छी तरह वाकिफ प्रशिक्षित पेशेवर कार्यरत होंगे। प्रवर्तन जम्मू (मध्य) के लिए हेल्पलाइन नंबर 9419157257, 9419126915, 7006963445, 9419187455, 8494000145 और 7889800627 हैं। इसी प्रकार, कठुआ (मुख्यालय लखनपुर) के लिए हेल्पलाइन नंबर 7780938794, 7006473528, 7889631158, 7889557748, 9419135215, 9419142557, 9419661577, 7006956379 और 7006298189 हैं।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि से बाढ़ का मलबा हटाने का दिया निर्देश

श्रीनगर, 2 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई अचानक बाढ और भूस्खलन से भारी नुकसान के मद्देनजर, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने कृषि और स्वामित्व वाली भूमि पर जमा गाद, रेत और अन्य मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

भूविज्ञान एवं खनन निदेशक एस पी रुकवाल द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि भूमि और नदी तटों पर रेत, गाद और बजरी के भारी जमाव हो गए हैं।

विभाग ने कहा कि इस जमाव से न केवल संपत्ति को नुकसान पहुँचा है बल्कि कृषि योग्य भूमि भी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है।

स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए जिला खनिज अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर लघु खनिज रियायत और खनन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित स्वामित्व वाली और कृषि भूमि से मलबा हटाने और उठाने का निर्देश दिया गया है। आदेश में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि निकासी गड्ढों या खाइयों द्वारा ज़मीन की सतह को नुकसान पहुँचाए बिना की जानी चाहिए निदेशालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाढ़ प्रभावित ज़िलों में कृषि और आजीविका की सुरक्षा के लिए मलबा हटाना ज़रूरी है और निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए ज़िला खनिज अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे।

जावेद राणा ने वनों की सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर दिया ज़ोर

जम्मू 02 सितंबर। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जम्मू संभाग की पर्यावरणीय चुनौतियों और प्रमुख वन एवं संरक्षण पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें मुख्य रूप से वनों का क्षरण, जैव-विविधता की हानि और प्रदूषण संबंधी चिंताएँ चर्चा का विषय रहीं। मंत्री ने क्षेत्र में वनों के संरक्षण हेतु कड़े उपाय अपनाए जाने पर बल दिया और प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र को और अधिक सशक्त एवं कठोर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से वनों और जल निकायों के समीप प्रदूषण स्तर की सख्त निगरानी करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान चेनाब घाटी, रियासी और उधमपुर क्षेत्रों की पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन और भूस्खलन की समस्या को लेकर भी चिंता जताई गई, जहाँ नाजुक भू-भाग पर दबाव बढ़ रहा है। अधिकारियों ने चल रहे वनीकरण और ढलान स्थिरीकरण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। इस पर मंत्री ने वैज्ञानिक योजना और भू-तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया।

यू.ए.ई. में भारत के राजदूत होंगे दीपक मित्तल

नई दिल्ली. 2 सितंबर। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1998 बैच के वरिष्ठ राजनयिक डॉ. दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, डॉ. दीपक मित्तल (आईएफएस 1998) को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल मौजूदा राजदूत संजय सुधीर की जगह लेंगे, जो 2021 से यूएई में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, डॉ. दीपक मित्तल जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले, दीपक मित्तल 2020 से 2022 तक कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2018-2020 के दौरान पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान डेस्क का नेतृत्व किया और 2014-2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। विशेष रूप से, 2021 में उन्होंने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानेकजई के साथ भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक राजनयिक मुलाकात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में नई गति आई, जिसने एक व्यापक और रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, फकजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपने भाई, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलकर मुझे खुशी हुई। बता दें कि यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, और यह भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी है। यूएई में बड़ी तादाद में भारतीय प्रवासी रहते हैं, और यह दोनों देशों के बीच मजबूत संपर्क को दर्शाता है।

सतीश शर्मा ने तवी नदी के जलस्तर का किया निरीक्षण

जम्मू 02 सितंबर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवाएँ एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा ने तवी नदी के तटबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया ताकि जलस्तर की स्थिति का जायज़ा लिया जा सके और बाढ़ से जुड़े संभावित खतरों के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन की तैयारी का आकलन किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान उनके साथ एडीसी जम्मू अनुस्या जम्वाल, तथा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं पीएचई, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री ने नदी तटों और आस-पास के निचले इलाकों में बसी आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें आपात स्थिति के लिए तैनात मशीनरी, उपलब्ध बचाव नौकाएँ, तैनात चिकित्सा एवं राहत दल और अस्थायी शरण शिविरों की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया।

ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि नदी जलस्तर की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए और मैदान स्तर के कर्मचारियों तथा नियंत्रण कक्षों के बीच तीव्र संचार व्यवस्था बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की जनता को तत्काल अलर्ट पहुँचाए जाएँ, ताकि स्थिति बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में शीघ्र निकाला जा सके। उन्होंने आगे यह भी ज़ोर दिया कि राहत केंद्रों में पर्याप्त राशन, पेयजल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएँ पहले से उपलब्ध हों। नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि अग्रिम प्रबंध किए जाएँ, ताकि विस्थापन की स्थिति में कोई परिवार कठिनाई का सामना न करे। व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए एक मज़बूत ढाँचा तैयार किया है, लेकिन निरंतर सतर्कता और समन्वित प्रतिक्रिया ऐसी प्रा.तिक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे शांति और सतर्कता बनाए रखें तथा प्रशासन के परामर्श और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पूर्ण सहयोग करें।

मानवीय पहल करते हुए मंत्री ने घोषणा की कि वह अपना दो माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे, ताकि राहत एवं पुनर्वास प्रयासों को मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे योगदान भले ही छोटे हों, लेकिन प्रा.तिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को समय पर मदद पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मंत्री ने कहा, फजनता की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जीवन एवं संपत्ति की रक्षा हेतु हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस कठिन घड़ी में हम अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन तब तक हाई अलर्ट पर रहेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती और यह भी दोहराया कि जोखिमों को कम करने व नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएंगे।